@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# साहस समाचार

राष्ट्रीय संस्करण

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, मंगलवार, 23 दिसंबर 2025, वर्ष-1, अंक-59, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

रहमान डकैत के हुकस्टेप को शिल्पा शेट्टी ने किया कॉपी

...पेज-8

## भारत के संस्थागत ढांचे पर भाजपा का कब्जा : राहुल गांधी

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया कि देश के संस्थागत ढांचे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, लेकिन विपक्ष को इसका मुकाबला करने के लिए रास्ता निकालना होगा।

जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हार्टी स्कूल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि खुफिया एजेंसियों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हथियार में तब्दील कर दिया गया है।

राहुल गांधी ने इस संवाद कार्यक्रम का एक वीडियो सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। उन्होंने कहा, हम भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं... हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला हो रहा है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हरियाणा की मतदाता सूची में ब्राजील की मॉडल का नाम 22 जगह पर था।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हम जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत में चुनावी मशीनरी में कुछ बुनियादी समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया, संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, जब आप हमारी खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी को देखते हैं तो पाते हैं कि इन्हें पूरी तरह से हथियार में तब्दील कर दिया गया है।

गांधी ने कहा, देखिए, भाजपा के लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के कितने मामले हैं? जवाब यह होगा कि एक भी नहीं। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर मामले विपक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था, अगर आप बड़े उद्योगपति हैं और कांग्रेस का सहयोग करने का इरादा रखते हैं, तो आपको धमकाया जाएगा। ईडी सीबीआई आ जाएगी।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भारत में इस तरह का माहौल है कि संस्थाओं को जिस तरह का काम करना चाहिए वह नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे को अपने ढांचे के तौर पर देखती है जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं देखती, क्योंकि उसने इन संस्थाओं का निर्माण किया है।

उन्होंने चुनावी चंदे का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा के पास कांग्रेस की तुलना में बहुत ज्यादा पैसे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ₹विपक्ष के रूप में हमें स्थिति का मुकाबला करने के लिए रास्ता निकालना होगा... लेकिन आपको समझना होगा कि हम सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय संस्थागत ढांचे पर हुए उसके कब्जे से भी लड़ रहे हैं। गांधी ने दिल्ली और भारत के कुछ अन्य बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति से जुड़े सवाल पर कहा कि उत्पादन और प्रदूषण में कोई विरोधाभास नहीं है, सिर्फ यह मायने रखता है कि आप किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उत्पादन के लिए किस तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, जो हमारे बड़े शहरों में प्रदूषण है उसका निदान उचित सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम किया जा सकता है।

### सार समाचार

#### अदालत ने क्रिश्चियन जेम्स की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** दिल्ली की एक अदालत ने कथित अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में हिरासत से रिहाई की मांग कर रहे क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की याचिका पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया। मिशेल ने इस आधार पर रिहाई की मांग की है कि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए सजा की अधिकतम अवधि सात साल पहले ही काट चुका है। याचिका पर सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजय जिंदल ने 23 दिसंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। बीस दिसंबर को, अदालत ने कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में मिशेल को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था।

#### अरावली को हुए नुकसान को और बढ़ा रही मोदी सरकार: कांग्रेस

**नई दिल्ली, एजेंसी।** कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अरावली पर्वतमाला को पहले हुए नुकसान को और बढ़ा रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट किये गए एक वीडियो को साझा किया, जिसमें गहलोत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने उस '100 मीटर' फॉर्मूले को क्यों मान्यता दी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2010 में ही खारिज कर दिया था।

## नेशनल हेराल्ड मामला : हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सोनिया-राहुल से जवाब मांगा

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति रवींदर डुडेजा ने गांधी परिवार और अन्य लोगों को मुख्य याचिका के साथ-साथ ईडी के उस आवेदन पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं है।

उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तारीख तय की। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और आर एस चीमा ने गांधी परिवार की ओर से पैरवी की।

निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के लिए प्राथमिकी के अभाव में धन शोधन के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणामस्वरूप अभियोग शिकायत (आरोपपत्र के समकक्ष) मान्य नहीं है।

अदालत ने कहा कि एजेंसी की जांच एक निजी शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी, न कि प्राथमिकी के आधार पर।

## बांग्लादेश ने बंद की वीजा सेवा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश ने नयी दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग और त्रिपुरा स्थित अपने मिशन में वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

इस घटनाक्रम से अवगत लोगों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के समूहों द्वारा उच्चायोग और मिशन के बाहर प्रदर्शन किये जाने के बाद वीजा सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर अपरिहार्य परिस्थितियों के मद्देनजर वीजा सेवाओं के निलंबन की जानकारी दी।

त्रिपुरा स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग ने भी रविवार को मिशन के बाहर विरोध प्रदर्शन होने के बाद वीजा सेवाओं को निलंबित करने की इसी तरह की घोषणा की।

समझा जाता है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीजा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए ढाका द्वारा नियुक्त एक निजी ऑपरेटर ने भी अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

## भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत पूरी होने की सोमवार को घोषणा की। यह समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों से आने वाले विभिन्न घरेलू उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुंच देगा। साथ ही इससे अगले 15 वर्ष में 20 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उपलब्ध होगा।

इस समझौते से अगले पांच वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को भेड़ के मांस, ऊन, कोयला और वनों एवं लकड़ी से बनी 95 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। समझौते के तहत न्यूजीलैंड को कीवी फल, शराब, कुछ समुद्री खाद्य पदार्थ, चेरी, एवोकाडो, पर्सिमन, शिशु 'फॉर्मूला', मनुका शहद और दूध 'एल्ब्यूमिन' जैसी कई अन्य वस्तुओं पर शुल्क छूट भी मिलेगी।

घरेलू किसानों और सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के हितों की सुरक्षा के लिए भारत राजनीतिक रूप से संवेदनशील दुग्ध क्षेत्र जैसे दूध, क्रीम, व्हे, दही तथा पनीर में कोई शुल्क छूट नहीं देगा।

इस समझौते के अंतर्गत शामिल न होने वाले अन्य उत्पाद वनस्पति उत्पाद (प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम), चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवों से प्राप्त वसा और तेल, हथियार व गोला-बारूद, रत्न एवं आभूषण, तांबा तथा उसके उत्पाद और एल्युमीनियम तथा उससे संबंधित वस्तुएं हैं।

इसने कुशल व्यवसायों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के लिए एक नए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मार्ग के माध्यम से कुशल रोजगार के रास्ते भी खोले हैं। इसमें किसी भी समय 5,000 वीजा का 'कोटा' शामिल होता है और अधिकतम तीन साल तक का प्रवास संभव होता है।

इसमें आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों जैसे भारतीय व्यवसायों के साथ-साथ आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं निर्माण जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिससे कार्यबल की आवाजाही एवं सेवा व्यापार को मजबूती मिलेगी। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने और इसके लागू होने में संभवतः करीब सात से आठ महीने लग जाएंगे। यह समझौता अमेरिका में 50 प्रतिशत शुल्क का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को 'ओशिनिया' क्षेत्र में अपने निर्यात को विविधतापूर्ण बनाने में मदद करेगा।

भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापार समझौता लागू कर चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा सोमवार को की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फोन पर बातचीत की जिसके बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता संपन्न होने की घोषणा की गई।

मार्च, 2025 में लक्सन की भारत यात्रा के दौरान बातचीत शुरू होने के बाद दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि नौ महीनों के रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत संपन्न की है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

यह मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को बेहद गहरा करेगा, बाजार पहुंच को बढ़ाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा। साथ ही दोनों देशों के नवोन्मेषकों, उद्यमियों, किसानों, एमएसएमई, छात्रों तथा युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा।

आधिकारिक बयान में कहा गया, दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ-साथ अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश पर विश्वास व्यक्त किया।

### न्यूजीलैंड ने आवाजाही के नियमों को उदार बनाया, भारतीय छात्रों को मिलेगा कार्य वीजा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत आवाजाही संबंधी प्रावधानों को उदार बनाया है। इससे भारतीय छात्रों को अध्ययन के बाद लंबी अवधि के कार्य वीजा प्राप्त करने की सुविधा मिलने के साथ योग प्रशिक्षकों तथा होटल में काम करने वाले रसोइयों (शेफ) सहित 5,000 भारतीय पेशेवरों को वहां काम करने की अनुमति मिल रही है। दोनों देशों ने सोमवार को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता के समापन की घोषणा की। उम्मीद है कि इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और यह लगभग सात से आठ महीनों में लागू हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह इस समझौते को मंजूरी दी थी। इस समझौते को न्यूजीलैंड की संसद से भी मंजूरी मिलनी बाकी है। समझौते के अनुसार, न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ छात्र आवागमन और अध्ययन के बाद कार्य वीजा संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कोई संख्यात्मक सीमा नहीं है और भारतीय छात्रों के लिए प्रति सप्ताह 20 घंटे काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, आवागमन के संदर्भ में, न्यूजीलैंड में अध्ययन करने जाने वाले छात्र अब डिग्री कोर्स करने पर दो साल के कामकाजी वीजा, ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री लेने या एसटीईएम (विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीजनियरिंग और गणित) विषयों में स्नातक होने पर तीन साल के कामकाजी वीजा और न्यूजीलैंड में स्नातकोत्तर अध्ययन करने पर चार साल के कामकाजी वीजा के लिए पात्र होंगे।

## अरावली को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रम: यादव

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सोमवार को कांग्रेस पर अरावली की नई परिभाषा के मुद्दे पर 'गलत सूचना' और 'झूठ' फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन किया जा सकता है।

यादव ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए 'पूरी तरह से प्रतिबद्ध' है। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में राजस्थान में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की अनुमति दी, लेकिन वह अब इस मुद्दे पर भ्रम, गलत सूचना और झूठ फैला रही है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित नई परिभाषा का उद्देश्य 'अवैध खनन पर अंकुश लगाना' और 'कानूनी रूप से टिकाऊ खनन' की अनुमति देना है तथा वह भी तब होगा जब भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) संपोषणीय खनन के लिए प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) तैयार कर लेती है। सूत्रों ने कहा कि आईसीएफआरई उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में ही खनन की अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अध्ययन अरावली परिदृश्य के भीतर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण-महत्वपूर्ण और बहाली-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का भी निर्धारण करेगा जहां खनन पर सख्त प्रतिबंध होगा। यादव ने कहा कि कानूनी रूप से स्वीकृत खनन वर्तमान में अरावली क्षेत्र के केवल एक बहुत छोटे हिस्से में होगा, जो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 37 अरावली जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.19 प्रतिशत है।

#### दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही

**नई दिल्ली, एजेंसी।** राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा और वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गयी। चौबीस घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 373 दर्ज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, 39 कार्यरत निगरानी केंद्रों में से 12 ने वायु गुणवत्ता के 'गंभीर' श्रेणी में होने का संकेत दिया, जबकि 27 ने 'बेहद खराब' वायु गुणवत्ता दर्ज की। गंभीर श्रेणी में आने वाले केंद्रों में आनंद विहार सबसे अधिक प्रदूषित रहा, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक 425 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही, इसके बाद नोएडा का स्थान रहा, जहां एक्यूआई 366 दर्ज किया गया।

**आईएमडी ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है**

## कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को कड़ाके की सर्दी की स्थिति रही, हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहा।

दिल्ली में कुछ समय के लिए कोहरे के कारण दृश्यता बाधित रही, साथ ही उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी ऐसी स्थिति रही।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है।

आईएमडी के अनुसार, राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक था, जबकि अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम था।

मौसम विभाग ने बताया कि पालम में सुबह आठ बजे मध्यम कोहरे के कारण दृश्यता सबसे कम 150 मीटर दर्ज की गई और धीरे-धीरे इसमें सुधार होने के बाद सुबह 9:30 बजे तक 400 मीटर हो गई। क्रिसमस के दिन (25 दिसंबर) दिल्ली में तापमान 'सामान्य के करीब' रहने का अनुमान है, आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा रहने का पूर्वानुमान है।

पंजाब और हरियाणा में सोमवार को भी शीतलहर का असर जारी रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से कुछ डिग्री अधिक था।

स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, अमृतसर में न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री अधिक 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना में न्यूनतम तापमान औसत से एक डिग्री अधिक 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 8.9 डिग्री सेल्सियस और करनाल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा।

कश्मीर में हाल में हुई वर्षा के कारण रात के तापमान में वृद्धि और दिन के तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में बर्फबारी या बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विज्ञान स्टेशन ने भाखड़ा बांध (बिलासपुर) के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों, ऊना जिले के कुछ हिस्सों और बल्ह घाटी (मंडी) के कुछ हिस्सों में 26 दिसंबर तक सुबह तड़के या सुबह और देर रात के दौरान घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि 28 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है।

## भारत को छोटी और लंबी अवधि के युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए: चौहान

**मुंबई, एजेंसी।**

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को कहा कि भारत को आतंकवाद को रोकने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अल्पकालिक, उच्च तीव्रता वाले संघर्षों और अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवादों के कारण दीर्घकालिक संघर्षों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल चौहान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि बहु-क्षेत्रीय अभियान अब विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता होंगे, जहां एक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर तुरंत महसूस होगा।

उन्होंने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना कहा, भारत को किस प्रकार के खतरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए? यह दो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हमारे दोनों विरोधी -एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और दूसरा परमाणु हथियारों से लैस देश है - इसलिए हमें उस स्तर की प्रतिरोधक क्षमता को भंग नहीं होने देना चाहिए।

सीडीएस ने कहा कि भारत का अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। उन्होंने कहा, हमें आतंकवाद को रोकने के लिए अल्पकालिक, तीव्र संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर।

#### ठगी के शिकार पूर्व आईजी ने खुद को गोली मारी

**पटियाला, एजेंसी।** भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी अमर सिंह चहल ने सोमवार को यहां अपने सुरक्षा गार्ड की राइफल से कथित तौर पर खुद को गोली मार ली जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। चहल ने एक पत्र में कथित रूप से कहा है कि साइबर ठगों ने खुद को धन प्रबंधन सलाहकार बताकर उनसे 8.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वरुण शर्मा ने बताया कि पंजाब के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चहल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चहल, फरीदकोट में 2015 में हुए बेअदबी विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित पुलिस गोलीबारी मामलों में आरोपियों में से एक हैं।

# मनरेगा का नाम बदलने की साजिश के खिलाफ जिला कांग्रेस का प्रदर्शन

## जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

**नोएडा, एजेंसी।**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदले जाने की कथित साजिश और केंद्र सरकार की गांधी विरोधी सोच के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्ध नगर ने सोमवार को सूरजपुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर इतिहास मिटाने, गरीबों के अधिकारों पर हमला करने और संविधान विरोधी मानसिकता अपनाने के आरोप लगाए।

जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की और कहा कि मनरेगा गरीब मजदूरों का अधिकार है, जिसे छीनने और उसका नाम बदलकर एक खास विचारधारा थोपने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी के नाम और उनके विचारों पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी के नाम से डरती है, इसी कारण वह योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास को तोड़-मरोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा करोड़ों गरीब मजदूरों के लिए जीवनरेखा है और इसका नाम बदलना केवल शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है। यह फैसला सरकार की संविधान विरोधी और जनविरोधी मानसिकता को उजागर करता है।

दीपक भाटी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पहले रोजगार खत्म करती है और फिर रोजगार की गारंटी देने वाली योजना का नाम बदलकर अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक योजना के नाम की नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और गांधीवादी मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने का निर्णय वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी गांव-गांव और ब्लॉक-ब्लॉक तक उग्र जन आंदोलन छेड़ेगी और भाजपा की जनविरोधी नीतियों को जनता के सामने बेनकाब करेगी।

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी श्री अनुराग सारस्वत के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मनरेगा का नाम यथावत रखने और गरीब विरोधी फैसलों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।

इस प्रदर्शन में मुकेश शर्मा, गौतम अवाना, रिज़वान चौधरी, सूबेदार सतपाल सिंह, महाराज सिंह नागर, अशोक पंडित, सतीश शर्मा, धर्मवीर सिंह, मोहम्मद तकी, शिव चौटाला, पुनीत मावी, अरविन्द रेक्सवाल, गुलाब सिंह, तनवीर अहमद, हबीब मास्टर, रमेश वाल्मीकि, मोहित भाटी अधिवक्ता, रमा नेय्यर, गजन प्रधान, नरेश शर्मा, बिन्नू भाटी, सुबोध भट्ट, नीरज शर्मा, अमित कुमार, आलोक शर्मा, रमेश जीनवाल, नदीम प्रधान, सचिन भाटी, पियूष जाटव, सन्नी सिंह, हैप्पी भाटी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

# नूंह में पानी निकासी के लिए अठारह करोड़ मंजूर

**चंडीगढ़/नूंह, एजेंसी।**

लंबे समय से जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अठारह करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सोमवार को यह जानकारी विधानसभा में दी गई। नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद की तरफ जलभराव को लेकर उठाए गए सवाल पर सरकार ने यजी जवाब दिया। विधानसभा सत्र के दौरान नूंह शहर और आसपास के इलाकों में जलभराव का मुद्दा प्रमुखता से उठा।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से सदन को बताया गया कि वर्ष 2025 में अत्यधिक बारिश के बाद अस्थायी उपाय किए गए। इसके तहत नौ स्थानों पर अस्थायी जल पंप लगाए गए और करीब 11,350 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए अठारह करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। विभाग ने आश्वासन दिया कि आगामी चार महीनों में ठोस कदम उठाकर नूंह को जलभराव से राहत दिलाई जाएगी।

वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से यह भी कहा गया कि जिला स्तर पर संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थायी योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायत, नशा और अन्य मुद्दे भी उठाए जलभराव के साथ-साथ विधायक आफताब अहमद ने सदन में ग्राम पंचायतों की स्थिति, नशे की बढ़ती समस्या और अन्य जनहित के विषय भी रखे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई सरपंच फंड की कमी से परेशान होकर इस्तीफा दे रहे हैं, जो चिंता का विषय है। नशे के खिलाफ समन्वित अभियान चलाने, पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने और नूंह में नशा उन्मूलन केंद्र व मनोचिकित्सकों की नियुक्ति की जरूरत बताई गई। इसके अलावा विधायक ने पलवल के टिकरी ब्राह्मण में बंद धार्मिक को इबादत के लिए खोलने की मांग की और फसल खराबे के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया गया। इन सभी विषयों पर सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।

# नोएडा में प्रेमी युगलों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह गिरफ्तार

**नोएडा, एजेंसी।**

उत्तर प्रदेश में नोएडा के पार्कों और सुनसान इलाकों में लोगों को निशाना बनाकर ब्लैकमेलिंग और लूटपाट करने वाले तीन शातिर आरोपियों को थाना सेक्टर-58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

नोएडा एडीसीपी शेव्या गोयल ने बताया कि आरोपी शहर के विभिन्न पार्कों में बैठे प्रेमी युगलों को अपना निशाना बनाते थे। ये आरोपी पहले चोरी-छिपे मोबाइल फोन से उनकी तस्वीरें और वीडियो बना लेते थे। इसके बाद खुद को किसी संगठन से जुड़ा हुआ या सामाजिक कार्यकर्ता बताकर कपल्स को धमकाते थे।

उन्होंने बताया कि ये लोग धमकी देते थे कि यदि इन्हें पैसे या मोबाइल फोन नहीं दिए तो उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। बदनामी के डर से कई लोग उनकी बातें मान जाते थे और पैसे देकर वहां से चले जाते थे।

नोएडा एडीसीपी ने बताया कि आरोपी पार्कों के साथ ही देर रात या सुनसान इलाकों में अकेले घूम रहे लोगों को भी अपना शिकार बनाते थे। मौका देखकर ये लोग डराकर या धमकाकर राह चलते लोगों के मोबाइल फोन छीन लेते थे।

थाना सेक्टर-58 पुलिस को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जो अलग-अलग पीड़ितों से छीने या ब्लैकमेलिंग के जरिए हासिल किए गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और क्या इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रितेश कुमार, गजेंद्र सोलंकी, पवन नाम के रुप में हुई है।

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई इस तरह की ब्लैकमेलिंग या लूटपाट का शिकार हुआ हो तो बिना डर के पुलिस से संपर्क करें। सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

# ग्रेटर नोएडा जीरो प्वाइंट पर किसान महापंचायत, आज उमड़ेगा किसानों का सैलाब

## आगरा से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक के किसान इस पंचायत में भाग लेकर अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे।

**ग्रेटर नोएडा, एजेंसी।**

ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर आज किसानों की एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे।

आगरा से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक के किसान इस पंचायत में भाग लेकर अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। महापंचायत की तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही थीं। जीरो प्वाइंट के नीचे कालीन और दरी बिछाकर बैठक की व्यापक व्यवस्था की गई है। मंच और साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। फ्लाईओवर के पिलरों पर किसानों से जुड़ी मांगों और पंचायत से संबंधित पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह आयोजन पूरी तैयारी और संगठित तरीके से किया जा रहा है।

आसपास ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों के माध्यम से भी किसान पहुंचते नजर आ रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान, सर्किल रेट में बढ़ोतरी, 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट का आवंटन, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को पूरी तरह लागू कराना, विस्थापन नीति में सुधार, प्रभावित परिवारों को रोजगार तथा आबादी निस्तारण जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।

किसानों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीन तो ली गई, लेकिन मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। किसान नेताओं का आरोप है कि बार-बार ज्ञापन देने और आंदोलन करने के बावजूद प्रशासन और प्राधिकरण उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी कारण आज की महापंचायत के जरिए सरकार और प्रशासन को एक मजबूत संदेश देने की रणनीति बनाई गई है। महापंचायत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। वहीं, किसानों ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर आज होने वाली यह किसान महापंचायत न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि आगरा से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक के किसानों के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है।

# छात्र से मारपीट के मामले में केस दर्ज

**ग्रेटर नोएडा, एजेंसी।**

सेक्टर पी-3 स्थित केंद्रीय विहार सोसाइटी में रहने वाले बीए के छात्र के साथ मारपीट के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने छह नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक केंद्रीय विहार सोसाइटी में अमन सोलंकी किराये के फ्लैट में रहते हैं। वह शहर के एक कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने न्यायालय को बताया कि वह 12 अक्तूबर को घर से भोजन करने के लिए निकले थे। वह सोसाइटी के टावर-8 के पास पहुंचे तो आशुतोष, आकाश, सिद्धार्थ, अंकित, आशीष, अमित और 10-12 लोग तरुण और एक अज्ञात युवक को पीट रहे थे। अमन ने मारपीट का कारण पूछा तो आरोपी उसके ऊपर भी उग्र हो गए और पिस्तौल तान दी। पीड़ित के विरोध करने पर फायरिंग की।

# जन्मजात बीमारी से पीड़ित बच्ची का सफल ऑपरेशन

**गाजियाबाद, एजेंसी।**

जन्म के पांच साल बाद दिल में छेद से पीड़ित बच्ची के सफल और निशुल्क ऑपरेशन होने से परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। मुरादनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. भारत भूषण ने बताया कि दो अगस्त 2020 को मंजू देवी ने सीएचसी मुरादनगर में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद ही परिजनों ने देखा कि बच्चा रोते समय नीला पड़ जाता था और सांस लेने में परेशानी होती थी। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आरबीएसके) टीम जन्म से 18 वर्ष तक के युवाओं में जन्मजात दोषों की पहचान कर समय पर मुफ्त इलाज सुनिश्चित कराती है। इसी कड़ी में 20 मई 2023 को आरबीएसके टीम ने धेधा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच में चिकित्सक डॉ. अनुपमा शर्मा और उनकी टीम को बच्ची में जन्मजात दोष पाया गया।

# सड़क हादसों में छात्र समेत दो घायल, हालत गंभीर

**ट्रांस हिंडन, एजेंसी।**

ट्रांस हिंडन जोन में हुए सड़क हादसों में एक छात्र समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पैदल जा रहे छात्र को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। वहीं, लिंक रोड क्षेत्र में सड़क के किनारे खड़े एक युवक को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों का गंभीर हालत में अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

मूलरूप से बिहार के मधुबनी जिला की रहने वाली खोड़ा निवासी कामिनी झा के अनुसार 15 दिसंबर को उनका 16 वर्षीय बेटा आर्यन झा स्कूल से घर आ रहा था। अभय खंड गौर ग्रीन चौराहे के पास बाइक ने उनके बेटे को टक्कर मार दी। इसमें उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ मौजूद दोस्तों ने बेटे को कौशांबी स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक नंबर के आधार पर पीड़िता ने 21 दिसंबर को इंदिरापुरम थाने में केस दर्ज कराया।

वहीं, भोपुरा के राजीव नगर निवासी अली शेर ने बताया कि उनका बेटा आमिर 14 दिसंबर को रात करीब 11 बजे एमके प्लेस के पास रिश्तेदार को लेने के लिए गया था। वहां पर रोड के किनारे खड़े होकर रिश्तेदार के आने का इंतजार कर रहा था, तभी दिल्ली की तरफ से आ रही पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसमें उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस के सहयोग से उनके बेटे को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज में व्यस्त रहने के कारण 21 दिसंबर को पीड़ित ने केस दर्ज कराया। दोनों घटनाओं में पुलिस मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।

# फरीदाबाद : निवेश के नाम पर 32 लाख की ठगी, पांच गिरफ्तार

**फरीदाबाद, एजेंसी।**

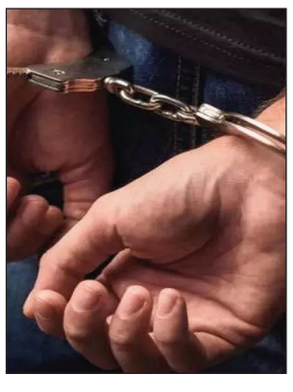

शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा पैसा कमाने का लालच देकर 32 लाख रुपए की ठगी मामले में साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने सोमवार को खाताधारक, खाता ऑपरेटर व खाता उपलब्ध करवाने वाले सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सेक्टर-15, फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि पिछले दिनों उसके व्हाट्सएप पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर एक संदेश प्राप्त हुआ। उक्त संदेश के माध्यम से उसे एसबीआई सिक्योरिटी ग्रुप नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया, जहां शेयर मार्केट में निवेश से संबंधित जानकारी दी जाती थी। ग्रुप के माध्यम से शिकायतकर्ता को एक वेब लिंक भेजा गया, जिसके जरिए एक फर्जी एप डाउनलोड करवाकर उसका खाता खुलवाया गया और निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। खाता खुलने के बाद उसे रोजाना निवेश के टिप्स दिए जाने लगे, जिनके झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने कुल 32 लाख 80 हजार रुपये का निवेश कर दिया। बाद में जब शिकायतकर्ता को ठगी का आभास हुआ तो उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर साइबर थाना सेंट्रल, फरीदाबाद में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने कार्रवाई करते हुए जितेन्द्र शर्मा निवासी मालवीय नगर, जयपुर, पराग जोशी निवासी गणेश नगर जयपुर, शिवम बोचिवाल निवासी रामगढ रुरल, शेखावती, राम सिंह वासी बगरु, जयपुर हाल गणेश नगर जयपुर व रोहित लाल यादव निवासी अकोदिया म.प्र. हाल बदरवास करनी विहार, वैशाली नगर जयपुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी टेलिग्राम के माध्यम से एक दुसरे से जुडे थे, रोहित मामले में खाताधारक है जिसके खाता में ठगी के 15 लाख रूपये आये और आरोपी पराग ने राहित का खाता लेकर आगे रामसिंह व राम सिंह खाता को आगे जितेन्द्र व शिवम को दिया था, जो खाता को ऑपरेट करते थे और खाता में आये पैसो को आगे ठगों के पास भेज देते थे। आरोपी पराग, रामसिंह व जितेन्द्र को जेल भेजा गया है वहीं शिवम व रोहित को चार दिन पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

# घर में घुसकर कक्षा नौ की छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास

**मोदीनगर, एजेंसी।**

निवाड़ी थानाक्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर कक्षा नौ की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा के भाई की बेरहमी से पिटाई की। अलग-अलग समुदाय का मामला होने के कारण तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निवाड़ी थाने पर हंगामा भी किया। जानकारी के अनुसार गांव में महिला परिवार के साथ रहती है।

उनकी 13 वर्षीय बेटी कक्षा नौ की छात्रा है। सोमवार सुबह महिला अपने पति के साथ खेत में चली गई और उनकी बेटी घर में अकेली थी। आरोप है कि इसी बीच पड़ोस में रहने वाला युवक घर के अंदर आ गया। आरोपी युवक गलत काम करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच छात्रा ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर चाचा का लड़का मौके पर पहुंच गया। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने फोन कर अपने साथी बुला लिए। आरोप है कि किशोरी के चाचा के लड़के के साथ मारपीट की गई। इस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

परिजन छात्रा को लेकर निवाड़ी थाने पहुंचे और तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में आनकानी की। इसके बाद बजरंग दल के मधुर नेहरा और निशांत त्यागी पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देखकर थानाप्रभारी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, जल्द ही उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे।

# रैंकिंग के जरिये सरकारी स्कूलों की शिक्षा और आधारभूत ढांचा मजबूत होगा

## 181 बिंदुओं पर स्कूलों की रैंकिंग तय की जाएगी

**फरीदाबाद, एजेंसी।**

शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी स्कूलों की रैंकिंग तैयार करवाएगा। रैंकिंग के आधार पर भी ही शिक्षा व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा निदेशालय ने योजना बनाई है। स्कूलों की रैंकिंग 181 बिंदुओं पर तय की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने निर्देश भी जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। स्कूलों में संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। स्टेम लैब, आईटीसी लैब, पुस्तकालय सहित शिक्षा संबंधी कई विषय वस्तु को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ ही अब सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन भी होगा। उस मूल्यांकन के आधार पर ही स्कूलों की रैंकिंग तय होगी। स्कूल की रैंकिंग शिक्षा स्तर को बताने के लिए पर्याप्त होगी। निष्पक्ष एवं पारदर्शी मूल्यांकन स्कूल सच पोर्टल के जरिये होगा। यह योजन अगले वर्ष एक अप्रैल से लागू होगा। इस योजना के जरिये शिक्षा निदेशालय को स्कूल में मौजूद शिक्षा संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर परिणाम सुधारना भी है। इन बिंदुओं के आधार पर तय होगा मूल्यांकन सरकारी स्कूलों की रैंकिंग के लिए शिक्षा निदेशालय ने एक 181 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इसमें से स्कूल में बच्चों की देखभाल व सुरक्षा, स्कूल भवन व सुविधाएं, शिक्षकों का प्रशिक्षण, समुदाय की भागीदारी, बच्चों के सीखने के परिणाम, शौचालय, स्कूल के पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल मैदान, खेल क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि, स्कूल का परिणाम, छात्र संख्या व उनकी उपस्थिति सहित कई बिंदु शामिल हैं। इनके आधार पर स्कूल की रैंकिंग तय होगी। स्कूल में सुविधाएं होंगी बेहतर इस योजना लागू करने से पूर्व सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके बाद योजना को लागू किया जाएगा। पोर्टल पर स्कूल की सुविधा संबंधी प्रत्येक जानकारी ऑनलाइन रहेगी। इससे आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि स्कूल में कौन-कौन सी सुविधाएं हैं और किस सुविधा का अभाव है। स्कूल किस रैंक पर है और लर्निंग आउटकम क्या है। इन सब की जानकारी होने से सुविधाओं एवं शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा। दो चरण में होगी योजना स्कूलों की रैंकिंग का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण जिले के सभी सरकारी स्कूलों को लिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में सभी निजी स्कूलों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि जिले में 379 सरकारी स्कूल हैं। इसमें प्राथमिक, मिडल, हाई स्कूल और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। दूसरे चरण में निजी स्कूलों को शामिल किया जाएगा। जिले में 800 से अधिक निजी विद्यालय हैं। अभिभावक जालसाजी से बच सकेंगे स्कूलों की रैंकिंग होने से अभिभावक जालसाजी से बच सकेंगे। हर वर्ष अभिभावक गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवा लेते हैं।उसके बाद परेशान रहते हैं। रैंकिंग सिस्टम होने से इसमें भी पारदर्शिता आएगी। अभिभावक गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के दाखिले से बचेंगे। शिक्षा निदेशालय के आदेश प्राप्त हुए हैं। उसके अनुरूप कार्य शुरू कर दिया है।

# गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

**गाजियाबाद, एजेंसी।**

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ के दौरान हत्या में वांछित दो बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम दिल्ली-सहारनपुर हाईवे की सर्विस लेन पर गढ़ी कट्टैया कट से आगे एक खाली प्लॉट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि डाबर तालाब क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने वाले दो बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गढ़ी कट्टैया से सभापुर अंडरपास की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सतर्कता बढ़ाते हुए उसी मार्ग पर चेकिंग शुरू कर दी।

कुछ ही देर में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक गढ़ी कट्टैया की ओर से आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया और मोटरसाइकिल मोड़कर खाली प्लॉट की ओर भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पीछे बैठे बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। इसके बाद घायल बदमाश और उसके साथी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम अफसर बताया, जबकि दूसरे आरोपी की पहचान शहजाद के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों ने दिनांक 11 दिसंबर को एसएलएफ वेद विहार, डीएलएफ निवासी सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या की थी। इस संबंध में थाना अंकुर विहार में पंजीकृत है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घायल बदमाश अफसर के खिलाफ लूट और चोरी के अलग-अलग राज्यों में करीब 12 केस दर्ज हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य आपराधिक मामलों की भी जांच की जा रही है।

RNI.No DLHIN/25/A2841 स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मे. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।
संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com
संपादक देवेंद्र सिंह तोमर
इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

# दिल्ली की हवा साफ करने के मिशन में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं : सिरसा

## "नो पीयूसी, नो फ्यूल" नियम लागू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा वाहनों की पीयूसी जांच हुई है।

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति पर तेज़ी से काम कर रही है। बीते चार दिनों से लागू ग्रैप-4 के सख़्त प्रावधानों के सकारात्मक असर अब ज़मीन पर दिखने लगे हैं और हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जा रहा है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि "नो पीयूसी, नो फ्यूल" नियम लागू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा वाहनों की पीयूसी जांच हुई है और सर्टिफिकेट्स दिए गए। साथ ही 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतर सके। उन्होंने कहा कि यह इस बात का साफ संकेत है कि सख्त प्रवर्तन सही दिशा में असर दिखा रहा है।

माननीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि सभी पीयूसी केंद्रों को आधुनिक और उन्नत मशीनों से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जांच में देरी न हो और नतीजे सही रहें। इसके साथ ही पीयूसी व्यवस्था को और भरोसेमंद बनाने के लिए थर्ड-पार्टी जांच प्रणाली लागू की जा रही है। परिवहन विभाग की तकनीकी टीमें लगातार मौके पर निगरानी कर रही हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

आज से दिल्ली भर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया है। जो भी औद्योगिक इकाई वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएगी, उसे तुरंत सील किया जाएगा। 31 दिसंबर तक ओईसीएम सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन न करने वाले उद्योगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

एमसीडी और डीपीसीसी मिलकर शहर में चल रहे अवैध और अनधिकृत औद्योगिक यूनिट्स की पहचान कर रहे हैं। ऐसे सभी यूनिट्स बंद किए जाएंगे। मंत्री ने कहा, "दिल्ली सरकार 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सिरसा ने बताया कि धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर दिन-रात सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लैंडफिल साइट्स पर रोजाना करीब 35,000 मीट्रिक टन कचरे की वैज्ञानिक तरीके से बायो-माइनिंग की जा रही है, ताकि पुराने कचरे के पहाड़ खत्म हों और धूल से होने वाला प्रदूषण घटे।

माननीय मंत्री ने शहर के जलाशयों को पुनर्जीवित करने की दिशा में हो रही प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जो जलाशय वर्षों से खत्म या अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं, उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत को आने वाले दिनों में उनके मूल स्वरूप में वापस लाया जाए। ये जलाशय धूल को कम करने और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।"

वर्क-फ्रॉम-होम निर्देशों को लेकर मंत्री ने साफ कहा कि ग्रैप-4 के तहत 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम का पालन न करने वाली निजी कंपनियों पर कार्रवाई होगी। सुविधा जरूरी है, लेकिन लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता।

एएनपीआर कैमरों में तकनीकी खामियों की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग इस मुद्दे को देख रहा है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन योजनाओं को उन्होंने संभाला, वहां भी लापरवाही रही। हमने सोचा था कि कम से कम ये कैमरे तो ठीक होंगे, लेकिन यहां भी शिकायतें सामने आ रही हैं।

सिरसा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग दस साल तक दिल्ली पर राज कर गए और प्रदूषण, बदइंतजामी और भ्रष्टाचार छोड़ गए, वे अब सिर्फ़ पोलिटिकल टूरिस्ट जैसे फोटो खिंचवाने और कार्यक्रमों में दिखने के लिए आते हैं।

# दर्पण-2.0 दिल्ली में जवाबदेह, स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया कदम: पंकज सिंह

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

पारदर्शी और परफॉर्मेंस आधारित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार बहुत जल्द ही डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण-2.0 शुरू करने जा रही है।

यह एडवांस्ड, यूनिफाइड परफॉर्मेंस-मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इसे एक रियल-टाइम, एनालिटिक्स-ड्रिवन प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। दर्पण-2.0 अलग-अलग सरकारी विभागों को मुख्य योजनाओं और सेवाओं के लिए एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराएगा, जिससे तेजी से परफॉर्मेंस के आधार पर फैसले लेने में मदद मिलेगी।

दर्पण-2.0 प्लेटफॉर्म कई एमआईएस सिस्टम को एक सिंगल विंडो, आसान इंटरफेस में इंटीग्रेट करके अलग-अलग डिपार्टमेंट में बिखरे हुए और असंगत (इनकंसिस्टेंट) डेटा की पुरानी चुनौती का समाधान करता है। इसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, लाइव प्रोग्रेस ट्रैकिंग, अर्ली-वॉर्निंग इंडिकेटर्स और तुलनात्मक एनालिटिक्स होंगे, जिससे सरकार को और ज्यादा जवाबदेही और कोऑर्डिनेशन से बेहतर फैसला लेने में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

दर्पण, कई राज्यों में प्रयोग किया हुआ एक सफल और सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, जिसे राजधानी दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जाएगा और सरकार की प्राथमिकता वाली जरूरी योजनाओं को सुरक्षित एपीआई के जरिए चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। इसे 12-16 हफ्तों में अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा, जिसके आखिर में सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी।

सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड दर्पण-2.0 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दर्पण-2.0 राजधानी दिल्ली में जवाबदेह, डेटा आधारित स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। डेटा साइलो को खत्म करके और डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस की रियल-टाइम जानकारी देकर यह प्लेटफॉर्म फैसला लेने वालों को तेजी से काम करने, सर्विस डिलीवरी को और बेहतर बनाने और यह पक्का करने में मदद करेगा कि हर योजना लोगों तक असरदार और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

यह पहल डिजिटल इंडिया विजन के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भविष्य में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और पब्लिक-फेसिंग डैशबोर्ड में भविष्य के विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखती है।

# फर्जी दवाओं और नकली कॉस्मेटिक्स रैकेट का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवाओं और फर्जी कॉस्मेटिक उत्पादों के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। सेल ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जो स्प्यूरियस दवाओं व नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग तैयार कर सप्लाई करता था।

दरअसल, यह मामला एफआईआर नंबर 360/25 के तहत दर्ज किया गया है और क्राइम ब्रांच थाना मामले की जांच कर रही है। इस केस में इससे पहले तीन आरोपियों को स्प्यूरियस दवाओं के निर्माण और सप्लाई की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को एक ऐसे प्रिंटिंग मॉड्यूल का सुराग मिला, जो नकली दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए रैपर और पैकेजिंग सामग्री सप्लाई करता था।

इसी कड़ी में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो नकली दवा 'क्लॉप-जी' और कॉस्मेटिक क्रीम 'स्कीन साइन' की पैकेजिंग बॉक्स सप्लाई करने में शामिल थे। पुलिस टीम ने राम रोड, दिल्ली स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा, जहां से 'स्कीन साइन' के रैपर तैयार करने वाली दो डाई फ्रेम बरामद की गईं। इस कार्रवाई के साथ ही एक सक्रिय प्रिंटिंग यूनिट का भंडाफोड़ हो गया, जो बड़े पैमाने पर स्प्यूरियस दवाओं की पैकेजिंग सप्लाई करता था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनिल सिंह रावत (46) और राहुल अग्रवाल (31) के रूप में हुई। दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। अनिल सिंह रावत राम रोड स्थित प्रिंटिंग प्रेस का संचालन करता है, जहां से स्प्यूरियस दवाओं के रैपिंग बॉक्स सप्लाई किए जाते थे। मौके से 'स्कीन साइन' रैपर बॉक्स तैयार करने वाली दो डाई फ्रेम्स बरामद किए गए। इस मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी राहुल अग्रवाल ने खाटू श्याम प्रिंटर्स, राम रोड से नकली दवाओं के रैपिंग बॉक्स की सप्लाई के ऑर्डर बुक किए थे।

पुलिस अब इस सिंडिकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की पहचान में जुटी है, जिसमें नकली दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल कच्चे माल के स्रोत, पैकेजिंग आपूर्ति श्रृंखला और वितरण नेटवर्क का खुलासा शामिल है।

यह कार्रवाई इंस्पेक्टर मनजीत कुमार के नेतृत्व में एएसआई कंवरपाल, हेड कॉन्स्टेबल विपिन, सोहनपाल, राजेश, अनुज और कांस्टेबल सचिन की टीम ने की। पूरी कार्रवाई एसीपी अनिल शर्मा की निगरानी में और डीसीपी आदित्य गौतम के दिशानिर्देशों में संपन्न हुई।

# प्रदूषण पर रेखा सरकार का कड़ा प्रहार, अब नहीं माफ होगा पीयूसी चालान

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कुछ निर्णायक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। इसी कड़ी में दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई प्रभावी निर्णय लिए गए। इनमें पीयूसी चालान को माफ न करना, दिल्ली एनसीआर में पूल व शेयर ई-बसें चलाना शामिल है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित पर्यावरण, परिवहन, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पीडब्ल्यूडी और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे कड़ा रुख उन वाहनों के प्रति अपनाया जो बिना वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) के सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर 10 हजार रुपए के भारी जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया कि अक्सर वाहन मालिक लोक अदालत का सहारा लेकर इस जुर्माने को बहुत कम करवा लेते हैं, जिससे दंड का भय समाप्त हो जाता है और लोग अपने वाहनों को प्रदूषण मुक्त कराने के प्रति गंभीर नहीं होते।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि इसके लिए सरकार को कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े, तो पीछे नहीं हटा जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्व वसूली नहीं, बल्कि नागरिकों को शुद्ध हवा देना है।

प्रदूषण कम करने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हुए दिल्ली सरकार शीघ्र ही ओला और उबर जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ संवाद करेगी। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पूल व शेयर के रूप में 'प्रदूषण रहित सवारी बसें' चलाने की संभावनाओं को तलाशना है। यदि ये कंपनियां इलेक्ट्रिक या प्रदूषण मुक्त बसें संचालित करती हैं, तो इससे सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि राजधानी को जीरो उत्सर्जन करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है।

राजधानी की सड़कों पर अनियंत्रित ई-रिक्शा यातायात जाम का एक बड़ा कारण बनते हैं। जाम के कारण वाहनों का ईंधन अधिक जलता है, जो सीधे तौर पर प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होता है। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार जल्द ही नई 'ई-रिक्शा गाइडलाइन' जारी करेगी। इन नियमों के माध्यम से ई-रिक्शा के संचालन क्षेत्र और उनके रूटों को व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि यातायात बाधित न हो और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे।

सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों के रूटों को युक्तिसंगत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार डीटीसी की पहुंच दिल्ली के हर क्षेत्र और हर गली तक होनी चाहिए। रूटों के वैज्ञानिक व युक्तिसंगत करने से आखिरी मंजिल तक कनेक्टिविटी सुधरेगी, जिससे लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक बस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और इन निर्णयों को तत्काल प्रभाव से जमीन पर उतारने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध एक व्यापक और बहुआयामी युद्ध लड़ रही है।

# दिल्ली में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

राजधानी के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के तहत नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में सामान्य श्रेणी की सीट के लिए दाखिले की दौड़ जारी है। वहीं, शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दी है। निदेशालय ने निजी स्कूलों से नर्सरी, केजी और पहली कक्षा की सीटों की जानकारी मांगी है। ऐसे में उम्मीद है कि इस श्रेणी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। निदेशालय ने सभी जिला उप शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की सही जीपीएस लोकेशन व सीट की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इस बार भी स्पष्ट किया है कि इन श्रेणी के दाखिले केंद्रीकृत होंगे। इसमें ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चे को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। निर्देशों में बताया है कि सभी निजी स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे प्रवेश स्तर में उस कक्षा की कुल संख्या के कम से कम 25 फीसदी बच्चों, जोकि आस-पास के कमजोर वर्ग और वंचित समूह से आते हैं, उन्हें दाखिला देंगे। सभी डीडीई को विभाग ने निर्देश दिया है कि वे अकादमिक सत्र के लिए डीओई में ईडब्ल्यूए, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के ऑनलाइन दाखिले के लिए खाली सीटों का विवरण जमा करें। गलत जानकारी से दाखिला हो सकता है रद्द अगर कोई छात्र उम्मीदवार दाखिला के लिए सफल होता है तो उसके घर से स्कूल की असल दूरी की जांच की जाएगी। वहीं, सीट अलॉटमेंट के बाद पता चलता है कि उम्मीदवार के घर की दूरी स्कूल से फिजिकल दूरी और ऑनलाइन मॉड्यूल में बताई गई दूरी से अधिक है तो डीडीई को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही, गलत जानकारी देने से दाखिला रद्द भी हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्कूलों के सही जीपीएस की जानकारी देनी होगी।

# दिल्ली: छात्र से चाकू की नोक पर लूट का मामला सुलझा, चार नाबालिग पकड़े गए

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में ट्यूशन से लौट रहे एक छात्र से चाकू की नोक पर हुई लूटपाट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से सोमवार को जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, 15-16 दिसंबर की रात वेलकम थाना पुलिस को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि कबीर नगर इलाके के 17 वर्षीय युवक को चाकू लगने की चोट के साथ भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। घायल छात्र ने पुलिस को बताया कि रात करीब 10 बजे वह ट्यूशन से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पांच लोगों ने उसे घेरकर हमला किया और चाकू मारकर 350 रुपए लूट लिए।

पीड़ित के इस बयान के आधार पर वेलकम थाने में एफआईआर नंबर 652/2025 दर्ज की गई। शुरुआत में मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया और वेलकम थाने के एसएचओ रूपेश खत्री की अगुवाई में जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय स्रोतों की मदद से सुराग जुटाए और शक की बुनियाद पर चार नाबालिगों (उम्र 14 से 16 वर्ष) को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के क्रम में चारों ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वह चाकू भी बरामद कर लिया जो वारदात में इस्तेमाल किया गया था।

पुलिस के अनुसार, एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6), 311 और 3(5) भी जोड़ी गई हैं। इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात में शामिल पांचवां आरोपी कौन था और उसकी भूमिका क्या थी।

# शराब के नशे में हुई कहासुनी बनी हत्या की वजह, आरोपित गिरफ्तार

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रेम नगर थाना पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। घटना में एक मजदूर की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपित बिहार भागने की फिराक में था।

रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने सोमवार को बताया कि 19 दिसंबर को प्रेम नगर थाना क्षेत्र से पीसीआर कॉल मिली कि एक मजदूर गंभीर हालत में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में मृतक की पहचान मुकेश (45) के रूप में हुई। वह बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक साइट पर मजदूरी करता था और मूलतः गांव जगतपुर, जिला बांका (बिहार) का रहने वाला था। प्रेम नगर थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मोबाइल क्राइम टीम और एफएसएल रोहिणी ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। पूछताछ में निर्माणाधीन मकान के मालिक ने बताया कि घटना के बाद से दो मजदूर मुंसी राय और विशु राय लापता हैं। तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपित आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बिहार की ओर भाग गए हैं।

पुलिस टीम ने रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से कई ट्रेनों की तलाशी ली। काफी मशक्कत के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस में दोनों की पहचान कर उन्हें बक्सर जंक्शन पर उतार लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपित मुंसी राय ने कबूल किया कि 18/19 दिसंबर की रात वह और मृतक मुकेश साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि पहले मुकेश ने ईंट से हमला किया, जिसके जवाब में मुंसी ने भी ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से मुकेश बेहोश होकर गिर पड़ा। विशु राय ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन दोनों घबराकर मौके से फरार हो गए। जांच में विशु राय के खिलाफ कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले, उसे प्रत्यक्षदर्शी माना गया है।

# अनाधिकृत कॉलोनियों में यमुना सफाई के नाम पर धन की बर्बादी बंद करे सरकार : देवेंद्र यादव

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार पर अनाधिकृत कॉलोनियों में यमुना सफाई के नाम पर गलत प्राथमिकताएं तय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार सीवर लाइन बिछाने जैसे स्थायी समाधान अपनाने के बजाय सेप्टिक टैंकों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च करने की योजना बना रही है, जो न तो यमुना को साफ करेगी और न ही आम लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान दे पाएगी।

देवेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि जब अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क का अभाव है, तो सरकार यमुना स्वच्छता अभियान के तहत 300 सेप्टेज सफाई मशीनें तैनात करने की घोषणा क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्लीवासियों को गुमराह करने के लिए इस योजना को यमुना सफाई से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि पिछले दस महीनों में यमुना सफाई को लेकर केवल घोषणाएं ही की गई हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सेप्टिक टैंकों की सफाई पर हर महीने करोड़ों रुपये खर्च करने के बजाय सरकार को अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाकर जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भावनात्मक मुद्दों के सहारे सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है।

श्री यादव ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को उन परियोजनाओं पर गंभीरता से काम करना चाहिए, जिनका उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने विशेष रूप से ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की 124 एमजीडी क्षमता वृद्धि परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार को इस पर ठोस प्रगति सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नजफगढ़ और टीकरी कलां जैसे सीवर लाइन से वंचित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कचरा उपचार के लिए छोटे संयंत्रों के निर्माण की आवश्यकता है, ताकि परिवहन से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सके।

देवेंद्र यादव ने इंटरसेप्टर सीवर परियोजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा जैसे प्रमुख नालों के किनारे सीवर लाइन बिछाकर कच्चे सीवेज को यमुना में जाने से पहले ही रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे यमुना में सीधे गिरने वाले अनुपचारित सीवेज की मात्रा में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से पुरानी और जर्जर सीवर लाइनों की तत्काल मरम्मत, बार-बार होने वाली रुकावटों को दूर करने और सीवेज नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों व अनाधिकृत बस्तियों को सीवेज प्रणाली से जोड़ने की मांग की। उनका कहना था कि बढ़ती आबादी को देखते हुए दिल्ली में सीवेज उपचार क्षमता और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में बड़ी मात्रा में अनुपचारित सीवेज सीधे यमुना में गिर रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2018 के तहत लगभग 150 निजी ठेकेदार सेप्टेज के संग्रह और निपटान का कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में हर माह लगभग 30 से 40 करोड़ लीटर सेप्टेज का संग्रह और निपटान किया जा रहा है।

# ओवरएक्टिंग करने वालों के लिए पार्टी में अवसर: सौरभ भारद्वाज

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। जहरीली हवा और बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा हमला बोला है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक व्यंग्यात्मक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री पर तंज कसा, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

सौरभ भारद्वाज द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में वह अभिनय करते हुए एक दृश्य प्रस्तुत करते नजर आते हैं, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक मापने को लेकर व्यंग्यात्मक संवाद दिखाया गया है। यह वीडियो हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने वायु गुणवत्ता सूचकांक और तापमान से संबंधित शब्दों का एक साथ उल्लेख किया था। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री की समझ और संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं।

इस व्यंग्य वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। एक उपयोगकर्ता ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए लिखा कि उन्हें भी किसी भूमिका के लिए मौका चाहिए और पूछा कि ऑडिशन का फॉर्म कहां मिलेगा। इस पर सौरभ भारद्वाज ने भी चुटीले अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ओवरएक्टिंग कर सकते हैं, कमजोर पटकथा लिख सकते हैं या जिनके पास ऐसे विचार हैं, उनके लिए पार्टी में अवसर मौजूद है। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया।

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली की वायु गुणवत्ता को लेकर हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। सोमवार को भी राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सौ के पार दर्ज किया गया। सुबह के समय कई इलाकों में स्थिति और भी गंभीर रही, जहां सूचकांक चार सौ के करीब या उससे ऊपर पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी हालात में तत्काल सुधार के आसार कम हैं।

वायु प्रदूषण को लेकर जहां आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है, वहीं यह मुद्दा एक बार फिर दिल्ली की राजनीति के केंद्र में आ गया है। जहरीली हवा के बीच आरोप-प्रत्यारोप और व्यंग्य के इस दौर ने सियासी माहौल को और अधिक गरमा दिया है।

# लगातार दूसरे साल एक दिन भी दिल्ली में 50 से नीचे नहीं आया एक्यूआई

**नई दिल्ली, साहस समाचार।**

राजधानी की हवा में पहले की तुलना में सुधार तो हुआ है लेकिन, लोग अभी अच्छे स्तर की साफ-सुथरी हवा के दिनों का इंतजार कर रहे हैं। यह लगातार दूसरा साल है जब दिल्ली में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 के अंक से नीचे आई हो। बता दें कि 50 से नीचे वाले सूचकांक को ही साफ हवा का सबसे अच्छा स्तर माना जाता है। दिल्ली में आमतौर पर ही प्रदूषक कणों का स्तर सामान्य से ज्यादा रहता है। लेकिन, मानसून के महीनों में अच्छी बारिश के बाद ज्यादातर प्रदूषक कण साफ हो जाते हैं और हवा की गुणवत्ता भी साफ-सुथरे स्तर पर पहुंच जाती है।

## संपादकीय

# बांग्लादेश में भारत विरोध की पराकाष्ठा

जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ है तब से बांग्लादेश में भारत विरोध की पराकाष्ठा हो रही है, ऐसा नहीं है कि भारत सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता, भारत ऐसी शैतानी ताक़तों को कुचलने में देर नहीं करेगा, परंतु सोचना ज़रूरी है कि बांग्लादेश में भारत विरोध उनके मूल में है या कुछ आतंकियों की महत्वाकांक्षाएं बांग्लादेश के साथ भारत में भी अस्थिरता चाहती हैं। बांग्लादेश का आम जन मानस भारत विरुद्ध नहीं है, ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भारी दबाव में काम कर रही है लेकिन उनकी समस्या यह है कि वे बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं। जबकि इस वक्त सख्त पॉलिटिकल सिग्नल देने की जरूरत थी। सरकार का काम अगले साल की शुरुआत में चुनाव कराना है लेकिन साथ ही उन्हें कानून-व्यवस्था भी बनाए रखनी है। अवामी लीग के बैन होने और उसके नेताओं के गायब होने से देश का संतुलन बिगड़ गया है। राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। पहले वहां एक स्थिर ध्रुव था जो अब नहीं है। इस खाली जगह को किसी संस्था ने नहीं बल्कि सड़क पर उतरी भीड़ ने भरने की निंदनीय कोशिश की है । यह भीड़ ऊर्जा से भरी है लेकिन बहुत ही बेसब्री और गुस्से में है, सड़क पर उतरी भीड़ की अपनी एक अलग लॉजिक होती है, उसका मकसद राजनीतिक समाधान निकालना नहीं होता। वह सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहती है। और यही बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी के सदर्न चीफ़ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सेवन सिस्टर्स को अलग-थलग कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और त्रिपुरा को एक साथ सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। नेशनल सिटिजन पार्टी इसी साल फ़रवरी में बनी थी और इसे बनाने वाले वही लोग हैं, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन शुरू किया था, इसी विरोध प्रदर्शन के बाद शेख़ हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी । हसनत अब्दुल्लाह बांग्लादेश से बैठकर ऐसे बोल रहा है जैसे भारत कोई खीर का कटोरा है जिससे सात चम्मच खीर निकाल ली जाएगी, मुझे लगता है कि भारत को ऐसे लोगों को कॉलर से खींचकर लाना चाहिए और बताना चाहिए कि भारत की हैसियत क्या है । अब भारत को ऐसी ताक़तों को कुचलना ही होगा, बांग्लादेश में बैठे कुछ साँप लगातर भारत के विरोध में ज़हर उगल रहे हैं, बांग्लादेश में बैठे ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि भारत कोई छोटा सा देश नहीं है जो तुम लोगों की नफ़रत हिंसक बकवास सुनेगा, भारत एक बार में ही अक्ल ठिकाने लगा देगा।

दुःखद अगर शेख़ हसीना सत्ता में होतीं तो बांग्लादेश जिस रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है, वैसा नहीं होता । शेख़ हसीना को उनके विदेश विरोधियों ने बहुत ही संकीर्ण नज़रिए से देखा । बांग्लादेश का मूल्यांकन ऐसे किया गया मानो वह मतदान प्रतिशत की समस्या से जूझता डेनमार्क हो, न कि एक नाज़ुक, अत्यधिक घनी आबादी वाला देश, जिसकी पृष्ठभूमि हिंसक इस्लामवादी इतिहास और गहरी त्रासदी से गुज़री राजनीतिक संस्कृति की रही है । शेख़ हसीना कोई क्रांतिकारी नहीं थीं बल्कि एक शत्रुतापूर्ण माहौल में एक स्थिर शक्ति के रूप में देश-निर्माता रहीं हैं, उन्होंने जमात और उसके सहयोगी संगठनों को नियंत्रण में रखा, नागरिक-सैन्य संतुलन बनाए रखा, किसी भी यथार्थवादी विकल्प की तुलना में अल्पसंख्यकों की बेहतर सुरक्षा की और बांग्लादेश को आर्थिक के साथ भू-राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखा । मैं बांग्लादेश में हुई इस हिंसक क्रांति को लेकर संशय में रहा हूँ । ऐसा नहीं था कि हसीना में कमियां नहीं थीं, बांग्लादेश एक गहराई से विभाजित समाज है । हसीना देश के सबसे हिंसक तत्वों के ख़िलाफ़ एक मज़बूत दीवार थीं। बांग्लादेश के बनने में भारत की अहम भूमिका रही है, ये तय बात है कि भारत ने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया होता, दख़ल नहीं दिया होता तो आज बांग्लादेश का कहीं नामों निशान नहीं होता।

# अरावली पहाड़ियों में खनन पर अदालत और सरकार

कैलाश चन्द्र

*अरावली में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति को लेकर 1980 के दशक से ही जनहित याचिकाएँ दाखिल होती रही हैं। इन याचिकाओं के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने कई ऐतिहासिक आदेश दिए। वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह जिलों की अरावली पहाड़ियों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध आज भी प्रभावी है।*

भारत की अरावली पर्वतमाला उत्तर और पश्चिम भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा प्रणाली की रीढ़ है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक होने के साथ ही यह मरुस्थलीकरण को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार, भूजल पुनर्भरण का अहम क्षेत्र और जैव विविधता का महत्वपूर्ण आश्रय भी है। ऐसे में हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह दावा किया जाना कि सरकार ने अरावली में खनन और निर्माण के लिए "ढील" दे दी है, स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करता है और इससे जुड़ा सच जानने के लिए प्रेरित करता है। इसी संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देना पड़ा है। उन्होंने इन आरोपों को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। वास्तव में इस पूरे विवाद को समझने के लिए तीन बुनियादी पहलुओं को स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है; अरावली का भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व, सुप्रीम कोर्ट के पुराने और नए आदेश तथा सरकार की वर्तमान संरक्षण नीति।

हम यदि गहराई से देखें तब अरावली पर्वतमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 39 जिलों में फैली हुई दिखाई देती है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए यह 'ग्रीन लंग्स' की तरह काम करती है। यही पहाड़ियाँ थार मरुस्थल को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती हैं। वर्षा जल को रोककर यह भूजल को रिचार्ज करती हैं। हवा के बहाव को नियंत्रित करती हैं और प्रदूषण के स्तर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। एनसीआर की जलवायु, वायु गुणवत्ता और जल सुरक्षा सीधे-सीधे अरावली की स्थिति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि दशकों से अरावली क्षेत्र में खनन और निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण और कई जगहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अरावली में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति को लेकर 1980 के दशक से ही जनहित याचिकाएँ दाखिल होती रही हैं। इन याचिकाओं के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने कई ऐतिहासिक आदेश दिए। वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह जिलों की अरावली पहाड़ियों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध आज भी प्रभावी है। इसके बाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक मैपिंग और पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (ईआईए) के बिना अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले वैज्ञानिक सर्वे फिर पर्यावरणीय योजना और उसके बाद ही किसी प्रकार की अनुमति, यह सिद्धांत स्थापित किया गया। इसमें भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये रोकें अस्थायी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और कई मामलों में स्थायी हैं। आम धारणा के विपरीत हर साल नई-नई रोकें नहीं लगतीं, किंतु एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वह वर्षों तक लागू रहता है।

*एनसीआर के संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं पर भी सख्त नियंत्रण रहेगा। जहां किसी क्षेत्र को लेकर संदेह होगा, उसे तब तक अरावली माना जाएगा जब तक वैज्ञानिक सर्वे कुछ और सिद्ध न कर दे। यह प्रावधान संरक्षण नीति को और अधिक कठोर बनाता है। ध्यातव्य हो कि मई 2024 में न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे असंगत मानदंडों को देखते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति में पर्यावरण मंत्रालय, चारों राज्यों के वन विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिनिधि शामिल रहे। समिति का उद्देश्य था अरावली की एक समान, वैज्ञानिक और कानूनी रूप से मजबूत परिभाषा तैयार करना।*

वर्ष 2025 में उच्चतम न्यायालय ने अरावली को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने सभी राज्यों से अरावली की एक समान, वैज्ञानिक और लागू करने योग्य परिभाषा तैयार करने को कहा और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया। यहीं से भ्रम की शुरुआत हुई। कुछ लोगों ने यह प्रचारित किया कि अब केवल पहाड़ी की चोटी से 100 मीटर ऊपर तक ही संरक्षण रहेगा और उसके नीचे खनन की छूट मिल जाएगी। निश्चित ही ये दावा अधूरा और पूरी तरह भ्रामक है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाया गया 100 मीटर मानदंड पहाड़ी की ऊँचाई को "स्थानीय राहत" के संदर्भ में परिभाषित करता है। इसका अर्थ यह है कि पहाड़ी का आधार यदि जमीन के भीतर 20 मीटर नीचे तक फैला है तो संरक्षण की गणना वहीं से होगी। यानी चट्टान की पूरी मोटाई, उसकी ढलानें और उससे जुड़ी घाटियां भी संरक्षण के दायरे में आती हैं। दूसरे शब्दों में यह नियम खनन को छूट देने के लिए नहीं है, उक्त संदर्भ में यह स्पष्ट करने के लिए है कि अरावली वास्तव में कहाँ तक फैली है। जबकि इससे पहले विभिन्न राज्यों में अलग-अलग परिभाषाओं के कारण भ्रम और दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार नई वैज्ञानिक परिभाषा के बाद अरावली क्षेत्र लगभग 1.44 से 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ माना गया है। इसमें से करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सीधे-सीधे संरक्षित श्रेणी में आता है। केवल 0.2 से 2 प्रतिशत तक का हिस्सा ही सैद्धांतिक रूप से खनन के लिए संभावित माना जा सकता है। किंतु यह "संभावित" शब्द भी महत्वपूर्ण है। इस छोटे से हिस्से में भी खनन तभी संभव है जब विस्तृत माइनिंग प्लान बने। वैज्ञानिक अध्ययन हो। पर्यावरणीय मंजूरी मिले और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (आईसीएफआरई) से अनुमोदन प्राप्त हो। व्यावहारिक रूप से यह छूट लगभग नगण्य है। दिल्ली की पूरी अरावली में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है और भविष्य में भी यहां किसी प्रकार की माइनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एनसीआर के संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं पर भी सख्त नियंत्रण रहेगा। जहां किसी क्षेत्र को लेकर संदेह होगा, उसे तब तक अरावली माना जाएगा जब तक वैज्ञानिक सर्वे कुछ और सिद्ध न कर दे। यह प्रावधान संरक्षण नीति को और अधिक कठोर बनाता है। ध्यातव्य हो कि मई 2024 में न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे असंगत मानदंडों को देखते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति में पर्यावरण मंत्रालय, चारों राज्यों के वन विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिनिधि शामिल रहे।

समिति का उद्देश्य था अरावली की एक समान, वैज्ञानिक और कानूनी रूप से मजबूत परिभाषा तैयार करना। इसकी सिफारिशों को 20 नवंबर 2025 के अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनने तक सभी नई खनन लीज पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर सरकार "ग्रीन अरावली" अभियान के तहत 39 जिलों में वनीकरण, जल संरक्षण और स्थानीय प्रजातियों की नर्सरी विकसित कर रही है। ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी, ई-चालान, हाईटेक वेइंग ब्रिज और जिला स्तरीय टास्क फोर्स के जरिए अवैध खनन पर निगरानी रखी जा रही है।

कुल मिलाकर यदि हम सार रूप में कहें तो अरावली को लेकर ढील या छूट की खबरें तथ्यात्मक नहीं हैं, यह बहुत भ्रामक हैं। न्यायालय के आदेशों और सरकार की नीतियों से इस क्षेत्र का संरक्षण कमजोर नहीं हुआ है, यह तो पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि अफवाहों और आधे-अधूरे तथ्यों के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों और न्यायिक आदेशों के आधार पर इस मुद्दे को समझा जाए। विकास और संरक्षण को आमने-सामने खड़ा करने की राजनीति से सावधान रहते हुए अरावली को बचाने का जो राष्ट्रीय संकल्प केंद्र सरकार और न्यायालय ने परस्पर दिखाया है, हमारा उसके साथ खड़ा होना ही समय की मांग है।

***(लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं।)***

# किसानों के कल्याण के हिमायती थे चौधरी चरण सिंह

रमेश सर्राफ धमोरा

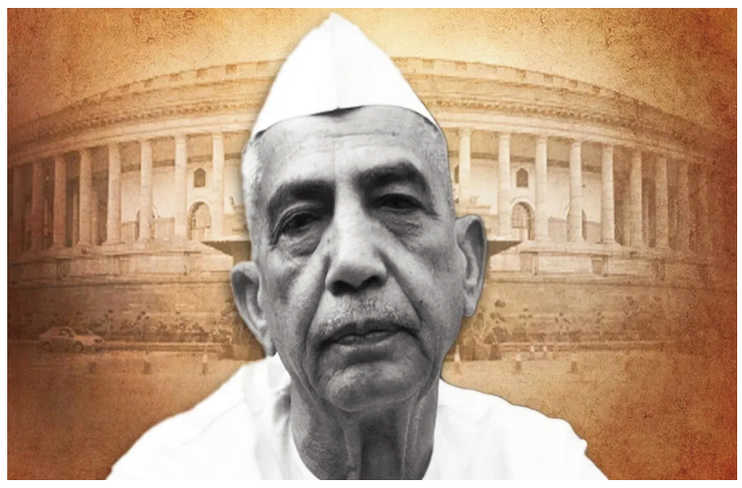

किसान राष्ट्र की जीवनधारा और अन्नदाता के रूप में सम्मानित भारत की समृद्धि की नींव हैं। उनका अथक परिश्रम देश का पेट भरता हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कायम रखता है और हर घर की ताकत सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है जो किसानों के अमूल्य योगदान का उत्सघव मनाता है। यह दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है जो ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अटूट वकालत के लिए प्रसिद्ध हैं। यह हमारे किसानों के अटूट समर्पण का सम्मान करने और देश की प्रगति को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने का क्षण है।

देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति नहीं विचारधारा थे। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा यह साबित करने की कोशिश की थी कि किसानों को खुशहाल किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। उनकी नीति किसानों व गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की थी। वो कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। जिस देश के लोग भ्रष्ट होंगे वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता।

चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसम्बर 1902 को गाजियाबाद जिले के छोटे से गांव नूरपुर के एक किसान चौधरी मीरसिंह के घर हुआ था। बाद में उनका परिवार नूरपुर से जानी खुर्द गांव आकर बस गया था। 1928 में चौधरी चरण सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर गाजियाबाद में वकालत प्रारम्भ की। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोडने के समर्थन में चरण सिंह ने हिण्डन नदी पर नमक बनाया जिस पर उन्हे 6 माह जेल की सजा हुई। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह गिरफ्तार किये गये। 1942 में अगस्त क्रांति के माहौल में चरण सिंह को गिरफ्तार कर डेढ़ वर्ष की सजा हुई। जेल में ही चौधरी चरण सिंह की लिखित पुस्तक शिष्टाचार भारतीय समाज में शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है।

चौधरी चरण सिंह को 1951 में उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय एवं सूचना विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1952 में डॉक्टर सम्पूर्णानंद के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें राजस्व तथा कृषि विभाग का दायित्व मिला। एक जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को खेती करने के अधिकार मिले। 1954 में उन्होने किसानों के हित में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। चरण सिंह स्वभाव से भी कृषक थे तथा कृषक हितों के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। 1960 में चंद्रभानु गुप्ता की सरकार में उन्हें गृह तथा कृषि मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश के किसान चरण सिंह को अपना रहनुमा मानते थे। उन्होंने कृषकों के कल्याण के लिए काफी कार्य किए। लोगों के लिए वो एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके भाषण को सुनने के लिये उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटा करती थी।

किसानो में चौधरी साहब के नाम से मशहूर चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तब 1967 में पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कहीं पत्ता भी नहीं हिल पाया था। 17 फरवरी 1970 को वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अपने सिद्धांतों से उन्होने कभी समझौता नहीं किया। 1977 में चुनाव के बाद जब केन्द्र में जनता पार्टी सत्ता में आई तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। केन्द्र में गृहमंत्री बनने पर उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वे उप प्रधानमंत्री बने। बाद में मोरारजी देसाई और चरण सिंह के मतभेद हो गये। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक चौधरीचरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस के सहयोग से भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने।

उन्होने किसानों की खुशहाली के लिए खेती पर बल दिया था। बचपन से ही उन्होंने गांव के किसानों, गरीबों के दुखः दर्द को नजदीकी से देखा जाना था। इसलिये उन्हें उनकी समस्याओं का बखूबी अहसास था। उनको जब कभी कहीं मौका मिलता वे गांव के किसानों की सेवा करने से नहीं चूकते थे। उनके दिल में हमेशा गांव के किसान ही बसे रहते थे। चौधरी चरण सिंह जीवन पर्यन्त गांधी टोपी धारण कर महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी बने रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके इसके लिए भी वो बहुत गंभीर रहते थे। उनका कहना था कि भारत का सम्पूर्ण विकास तभी होगा जब किसान, मजदूर, गरीब सभी खुशहाल होंगे। चौधरी चरण सिंह की गिनती हमेशा एक ईमानदार राजनेता के तौर पर की जाती है। उन्होंने जीवन पर्यन्त किसानों की सेवा को ही अपना धर्म माना और अपने अंतिम समय तक देश के गांव में रहने वाले किसानों, गरीबों, दलितो, पीड़तों की सेवा में ही पूरी जिंदगी गुजारी। चौधरी चरण सिंह जाति प्रथा के कट्टर खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह एक कुशल लेखक भी थे। उनका अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया। 29 मई 1987 को 84 वर्ष की उम्र में जब उनका देहान्त हुआ तो देश के किसानो ने सरकार में पैरवी करने वाला अपना नेता खो दिया था। लोगों का मानना था कि चरण सिंह से राजनीतिक गलतियां हो सकती हैं लेकिन चारित्रिक रूप से उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। इतिहास में उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह ने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलन्द करते हुये आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार का अन्त ही देश को आगे ले जा सकता है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 60 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हमारी सम्पन्नता हमारे कृषि और किसानों पर निर्भर करती है। भारतीय किसान का सर्वत्र सम्मान होता है। ये दिन रात कड़ी मेहनत कर सम्पूर्ण भारतवासियों के लिए अन्न एवं सब्जियां उत्पन्न करता हैं। किसानों को कठिन परिश्रम के पश्चात भी बहुत कम लाभ होता है। किसानों को आज भी कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज देश के किसान कर्ज में डूबे हुये हैं। उनको उनकी उपज का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते देश में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहें हैं।

चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां किसानो को झांसा देकर उनके वोट बटोर लेती है। फिर किसी का ध्यान किसानो की समस्याओं के समाधान करने की तरफ नहीं जाता है। ऐसे में आज देश के किसानो को चौधरी चरणसिंह जैसे सच्चे किसान हितैषी नेता की जरूरत है। जो उनके हक में खड़ा होकर किसानो की आवाज बुलन्द कर सके व उनका वाजिब हक दिला सके। चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के सहयोग से कुछ समय के लिये देश के प्रधानमंत्री बन कर उन्होने देश में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ बने एक मजबूत गठबंधन को तोड़ा था। उससे उनकी प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात पहुंचा था।

अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने 2001 में हर वर्ष 23 दिसम्बर को चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने की जो परम्परा शुरू की थी उससे जरूर उनको साल में एक दिन याद किया जाने लगा है।

# हिन्दुओं की वैश्विक है दर्दनाक पीड़ा

जब कोई पिता यह कहता है कि उसे अपने बेटे की मौत की खबर पुलिस, प्रशासन या सरकार से नहीं फेसबुक से मिली है, तब यह साफ हो जाता है कि उसका ये दर्द पूरे समाज और राज्य की सामूहिक नैतिक विफलता का परिणाम है। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में गारमेंट फैक्टरी में काम करने वाले दीपू चंद्र दास के पिता रवि लाल दास का दर्द आज इसी विफलता की गवाही दे रहा है। उनका बेटा परिवार का इकलौता कमाने वाला था। दिव्यांग पिता, मां, पत्नी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, किंतु अब वह दुनिया में नहीं, उसे तो इस्लामिक जिहादी कट्टर भीड़ ने घेरकर पीटा, पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया और फिर उसके जले हुए शरीर को सार्वजनिक रूप से टांग कर जश्न मनाया है।

दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या कोई अचानक भड़का उन्माद नहीं है। यह उस लंबे और बार-बार दोहराए गए पैटर्न की कड़ी है जिसमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को चुनकर निशाना बनाया जाता रहा है। 1951 में जिस देश में हिंदुओं की जनसंख्या 22 प्रतिशत थी, आज वो घटकर 8 प्रतिशत से भी कम रह गई है। यह गिरावट किसी सामान्य सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन से नहीं आई है। इसके पीछे दशकों का डर, हिंसा, संपत्ति लूट, मंदिरों पर हमले, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दीपू चंद्र दास जैसे अब तक अनेक लोगों को षड्यंत्र से, बल पूर्वक मार देने का झूठे आरोपों का इतिहास है। दीपू की हत्या उस समय हुई जब ढाका में छात्र नेता उस्मान शरीफ हादी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही थी। बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि ऐसे आंदोलनों का अंत अक्सर हिंदुओं पर हमलों से होता रहा है। कभी छात्र आंदोलन, कभी राजनीतिक असंतोष और कभी किसी एक घटना की आड़ में भीड़ को उकसाया जाता है और उसका निशाना हिंदू बस्तियां, मंदिर और आम नागरिक बनते हैं। हर बार यह संयोग नहीं हो सकता है, यह तो यहां एक स्थापित ढांचा बन गया है। इस पूरी प्रक्रिया में ईशनिंदा का आरोप सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है, जिसमें भीड़ को उकसाया जाता है, ये कहकर की उसने हमारे नबी या कुरान का अपमान किया है। निर्वासित लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तसलीमा नसरीन के अनुसार दीपू पर उसके ही एक मुस्लिम सहकर्मी ने झूठा आरोप लगाया था। पुलिस ने पहले दीपू को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया। दीपू ने स्पष्ट कहा था कि उसने पैगंबर के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, किंतु उसकी कौन सुननेवाला था! पुलिस ने कट्टरपंथी दबाव में उसे भीड़ के हवाले कर दिया! सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो इस बर्बरता को किसी संदेह से परे ले जाते हैं। कहीं दीपू थाने में बैठा दिखता है। कहीं सैकड़ों लोगों की भीड़ उसे घेरकर पीटती है। कहीं उसे नग्न कर प्रताड़ित किया जाता है और कहीं पेड़ से लटकाकर जिंदा जलाया जाता है। ये दृश्य एक हत्या के आगे बांग्लादेश में आज उस भय के दस्तावेज हैं जिसमें बहुत मुश्किल में रहते हुए कहना होगा हिंदू आज यहां सांस ले रहे हैं।

एक नजर देखें तो यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता है, पिछले एक साल में ही अनेक हिन्दू विरोधी हिंसा की भयंकर घटनाएं यहां घटी हैं। दिसंबर 2024 में आकाश दास के खिलाफ ईशनिंदा की अफवाह फैली और 130 हिंदू घर तथा 20 मंदिर जला दिए गए। नवंबर 2024 में करीमगंज उपजिला में रिदॉय रोबी दास की हत्या कर दी गई। अक्तूबर 2024 में फरीदपुर जिले में हृदय पाल नामक छात्र पर कॉलेज में हमला किया गया। चटगांव में प्रांत तालुकदार को अगवा कर प्रताड़ित किया गया। खगराचारी और रंगमती में धनंजय और रुबेल त्रिपुरा की हत्या अफवाहों के आधार पर हुई। घटनाएं अलग हैं पर तरीका एक है।

हिन्दू हिंसा से जुड़े सवाल आज सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहे हैं। पिछले वर्षों में पूरी दुनिया में हिंदुओं को उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों पर भीड़ द्वारा हत्या आम होती जा रही है। सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक प्रियांथा कुमारा को जिंदा जलाया जाना इसी उन्मादी मानसिकता का उदाहरण है जिसका असर वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर भी पड़ा है। सिंध प्रांत समेत पूरी पाकिस्तान से आए दिन खबरें आती हैं कि बेटी तो बेटी मां तक को जिहादी मानसिकता वाले इस्लामिक लोग अगवा कर ले रहे हैं।

# अजमेर दरगाह में पीएम मोदी की चादर पेश, रिजिजू ने की चादरपोशी

**अजमेर, एजेंसी।**

अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के अवसर पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे और परंपरागत तरीके से दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई। चादरपोशी के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों के नाम पढ़कर सुनाया।

कार्यक्रम को लेकर दरगाह परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह चादर प्रधानमंत्री, सरकार और देशवासियों की ओर से है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते वे स्वयं यहां पहुंचे हैं और जो भी संदेश देंगे, वही प्रधानमंत्री का संदेश होगा। उन्होंने स्वयं को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि अजमेर दरगाह आकर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ करने का अवसर मिला है। चादर पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिलखाने पहुंचे।

# विकसित भारत के निर्माण में सामूहिक प्रयास जरूरी: उपराष्ट्रपति

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं और इसमें भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि रक्षा सेवाओं के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन देश की सुरक्षा क्षमता को सीधे प्रभावित करता है।

आईडीएएस के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवकों को ज्ञान के साथ-साथ चरित्र, विनम्रता और संवेदनशीलता को भी अपने कार्य व्यवहार में शामिल करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से 'सेवा भाव और कर्तव्य बोध' को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की सेवा करने का अवसर सौभाग्य के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा लेखा विभाग की 275 वर्षों से अधिक पुरानी गौरवशाली परंपरा रही है और यह भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सिविल सेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। समावेशी विकास और अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाना अमृत काल का प्रमुख उद्देश्य है, जिसे साकार करने में युवा अधिकारियों की ऊर्जा और नवाचार निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन अनिवार्य है। उन्होंने सार्वजनिक धन के प्रबंधन में ईमानदारी, पारदर्शिता, सतर्कता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने तेजी से बदलते तकनीकी युग में सतत क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए आईजीओटी कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के प्रति अनुकूलन, नवाचार, नैतिक प्रशासन और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित भारत की यात्रा में सिविल सेवकों की पहचान बननी चाहिए।

कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय और वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) राज कुमार अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# हुमायूं कबीर ने की नई पार्टी की घोषणा

**मुर्शिदाबाद, एजेंसी।**

पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर सुर्खियों में आए तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पूर्व घोषणा के अनुसार सोमवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक ऐलान कर दिया। उनकी नई पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा गया है। पार्टी की घोषणा के साथ ही हुमायूं कबीर ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिया।

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उम्मीदवारों की सूची में एक से अधिक 'हुमायूं कबीर' का नाम शामिल है। इसका मतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों को 'हुमायूं कबीर' नाम के उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ेगा। इसे जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर ने एक बड़ा राजनीतिक 'सरप्राइज' बताया।

विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वह खुद रेजीनगर और बेलडांगा विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे और दोनों ही सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रानीनगर विधानसभा सीट से भी एक अन्य हुमायूं कबीर को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। यह वही हुमायूं कबीर हैं, जो 2016 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे, हालांकि तब उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी।

इतना ही नहीं, भगवानगोला सीट से भी एक और हुमायूं कबीर को उम्मीदवार बनाया है, जो पेशे से व्यवसायी हैं। हुमायूं कबीर ने यह भी संकेत दिया कि बीरभूम जिले से भी एक अन्य हुमायूं कबीर को उम्मीदवार बनाया जाएगा, हालांकि उनके नाम की औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।

नई पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगी। जनता उन्नयन पार्टी की ओर से कई हिंदू उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए गए हैं। मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट से मनीषा पांडे और बालिगंज से निशा चट्टोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा राज्य के कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बंगाल के लोगों का विकास है और बहुत जल्द पार्टी का चुनावी घोषणापत्र (इस्तीहार) भी जारी किया जाएगा।

## ज्योतिष महाधिवेशन में छाया रहा लव जिहाद का मुद्दा

**उज्जैन, एजेंसी।** मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन का सोमवार को सामाजिक सरोकारों पर केंद्रित विमर्श और प्रस्तावों के साथ समापन हुआ। देशभर से आए 500 से अधिक विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। महाधिवेश में लव जिहाद का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान ज्योतिषियों ने बेटियों को लव जिहाद से बचाने के ज्योतिष संगत उपाय भी बताए। ज्योतिषियों ने कुंडली में शुक्र-चंद्रमा के साथ छठें, आठवें या बारहवें स्थान पर होने, शनि-चंद्रमा और केतु गृह के एक साथ बैठने पर लव जिहाद का काल बनने का दावा कर उससे बचने के उपाय बताए।

## असम के खेरनी में विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, पुलिस फायरिंग में तीन घायल

**कार्बी आंगलोंग, एजेंसी।**

कार्बी आंगलोंग जिले के खेरनी क्षेत्र में सोमवार को सड़क अवरोध को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। आक्रोशित भीड़ ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलिराम रोंगहांग के पुराने आवास में आग लगा दी।

सूत्रों के अनुसार, अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों लोग खेरनी में सड़क पर उतर आए और मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान हुई पुलिस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस फायरिंग की खबर फैलते ही प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने तुलिराम रोंगहांग के पुराने आवास में आग लगा दी। सूचना मिलते ही दमकल और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया। क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।

प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस फायरिंग और आगजनी की घटनाओं की जांच शुरू कर दी गई है।

**सार समाचार**

## नीतीश कुमार ने मोदी और शाह से की मुलाकात

**नई दिल्ली, एजेंसी।** बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से यहां मुलाकात की। इस दौरान केन्द्रीय मत्स्य पालन,पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रचंड जनादेश के बाद आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन और नेतृत्व में देश एवं बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान विकसित बिहार के लक्ष्यों पर बहुमूल्य मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमित शाह ने एक्स पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भेंट हुई। मोदी और नीतीश सरकार प्रदेश में जनकल्याण एवं सुशासन को और अधिक ऊँचाई देने के लिए कटिबद्ध हैं।

## रेल किराये में एक पैसा प्रति किमी की वृद्धि पर राजनीति नहीं होनी चाहिए: जोशी

**हुबली, एजेंसी।**

रेलवे टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि बढ़ोतरी केवल एक पैसा प्रति किलोमीटर की हुई है। इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय गरीब और आम यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जोशी यहां हुबली में मीडिया से वार्ता कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में

उन्होंने कहा, जब मैं विपक्ष में था, तब मैंने लोकसभा में रेल किराए में वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब स्थिति अलग थी, लेकिन मोजूदा सरकार ने जनता पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला है। किराए में सिर्फ एक पैसा की वृद्धि हुई है। जोशी ने कहा कि स्थानीय बस के किराए में हुई बढ़ोतरी की तुलना में रेलवे के किराए में हुई बढ़ोतरी बहुत कम है। यह निर्णय गरीब और आम यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। केंद्र सरकार ने जनता की मांग को देखते हुए रेल सेवाओं को बढ़ाने, स्वच्छता और सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

## विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी द्रमुक

**चेन्नई, एजेंसी।** तमिलनाडु में आगामी 2026 विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी-अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) की सांसद और पार्टी की उप-महासचिव एम.के. कनिमोझी की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में द्रमुक के चुनावी घोषणा पत्र सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए द्रमुक ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। द्रमुक के महासचिव ने घोषणा की कि 2026 के चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।

# बीते 11 वर्षों में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में आया बड़ा बदलाव: अनुप्रिया पटेल

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 819 हो गई है। इसी तरह एमबीबीएस सीटें 51 हजार से बढ़कर 1.28 लाख और पीजी सीटें 31 हजार से बढ़कर लगभग 82 हजार हो गई हैं। एम्स की संख्या भी 7 से बढ़कर 23 हो गई है। सोमवार को वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के 7वें दीक्षांत समारोह में अनुप्रिया पटेल ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदार सेवक होते हैं, इसलिए सेवा भाव कभी खत्म नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज देश में 1.82 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं, जो लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई योजना के तहत देश के 62 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने जन औषधि योजना और अमृत फार्मेसी का भी उल्लेख किया, जिनसे सस्ती दवाएं मिल रही हैं। उन्होंने मेडिकल छात्रों से अपील की कि वे अपने पेशे में ईमानदारी, करुणा और मानवता को हमेशा बनाए रखें और गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा करें।

इस समारोह में 217 पोस्टग्रेजुएट, 136 अंडरग्रेजुएट और 40 सुपर-स्पेशलिटी छात्रों को डिग्रियां दी गईं। इसके अलावा 43 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा, कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय तथा डॉ. सुनीता शर्मा, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) भी उपस्थित रहे। इसके साथ वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) संदीप बंसल, प्रो. (डॉ.) गीतिका खन्ना, (प्रिंसिपल, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल), प्रो. (डॉ.) चारु बंबा, चिकित्सा अधीक्षक, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

## सिंधिया ने त्रिपुरा, मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

**नई दिल्ली, एजेंसी।** केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को यहां त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को लेकर उच्चस्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा की गई।

सिंधिया ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट' विजन से पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत का गेटवे बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है। बैठक में मल्टीमॉडल और डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, सिक्किम के प्रमुख अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले सिंधिया ने एक अखबार में प्रकाशित आलेख में पूर्वोत्तर भारत में हो रहे विकास के बारे में कहा कि अब तक करीब 4.48 ट्रिलियन रुपये निवेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में होने का रास्ता साफ हुआ है।

# राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है केंद्र सरकार: गौतम

**पटना, एजेंसी।**

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के अनुसूचित जाति (एससी) विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने का आरोप लगाया।

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब डॉ. भीमराव अंबेडकर काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार ने इस आवश्यकता को समझते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) लागू किया, ताकि गांवों में ही लोगों को रोजगार मिले और कोई भूखा न रहे। योजना के तहत खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती थी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को मजबूत करने और गांवों की जरूरत के अनुसार काम तय करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार इस योजना को धीरे-धीरे खत्म करने पर आमादा है। गौतम ने आरोप लगाया कि महिलाओं, मजदूरों और युवाओं को हर स्तर पर ठगा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिखावे के लिए 100 दिन की जगह 125 दिन का काम घोषित किया, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं से अधिकार छीन लिए गए और रोजगार की गारंटी भी कमजोर कर दी गई। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अब मनरेगा के तहत कार्य तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया है और पहले से आर्थिक दबाव झेल रही राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 प्रतिशत खर्च का भार उठाना किसी भी राज्य के लिए संभव नहीं है और इसी बहाने इस योजना को बंद करने की साजिश रची जा रही है।

योजनाओं के नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गौतम ने कहा कि यह सरकार नई योजनाएं लाने के बजाय पुरानी योजनाओं के नाम बदलने का काम कर रही है।

## हरिद्वार में तीन दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ शुरू

**हरिद्वार, एजेंसी।** सोमवार को हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में तीन दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ का उद्घाटन सोमवार को शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आयुर्वेद से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

इस मौके पर शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज ने कहा कि आयुर्वेद और योग के नाम पर जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं।

जब आयुर्वेद महाकुंभ में मंथन होगा तो ऐसी ताकतें अलग हो जाएंगी और उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

## नौसेना को मिला नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'अंजदीप'

**कोलकाता/चेन्नई, एजेंसी।**

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को वर्ष 2025 का अपना पांचवां युद्धपोत सौंपकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए तैयार उथले जलयान 'अंजदीप' को सोमवार को चेन्नई बंदरगाह पर औपचारिक रूप से नौसेना के हवाले किया गया। यह इस श्रेणी के आठ पोतों में तीसरा जलयान है, जिनका निर्माण जीआरएसई कर रहा है।

'अंजदीप' जीआरएसई द्वारा निर्मित 115वां युद्धपोत और भारतीय नौसेना को सौंपा गया 77वां युद्धपोत है। इसे पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी (तकनीकी) रियर एडमिरल गौतम मारवाहा, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित ने स्वीकार किया। इससे पहले वर्ष 2025 में जीआरएसई ने उन्नत निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट 'हिमगिरि', दो पनडुब्बी रोधी उथले जलयान 'अर्नाला' और 'अंद्रोथ', तथा विशाल सर्वेक्षण पोत 'इक्षक' नौसेना को सौंपे थे, जिन्हें बाद में सेवा में शामिल कर लिया गया।

# प्रधानमंत्री ने पंजाब को शहरी बुनियादी ढांचे की ऐतिहासिक सौगात दी : चुग

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अटल मिशन फॉर रिजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन( अमृत 2.0) योजना के तहत पंजाब को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति राज्य के शहरी विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह केवल बजटीय आवंटन नहीं, बल्कि पंजाब की वर्षों से उपेक्षित शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने की एक ठोस पहल है।

चुग ने विशेष रूप से अमृतसर को 135.49 करोड़ रुपये की सर्वोच्च राशि दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह पवित्र नगरी के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की गहरी समझ का प्रतीक है। स्वच्छ जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, जल निकायों का पुनर्जीवन और हरित क्षेत्रों का विकास — ये सभी कार्य अमृतसर की गरिमा और वैश्विक पहचान को और सुदृढ़ करेंगे।

सोमवार को मीडिया से बातचीत में तरुण चुग ने कहा कि अमृतसर केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, बलिदान और भारतीय सभ्यता की आत्मा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस संवेदनशीलता के साथ इस पवित्र नगरी के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

### भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इंदौर पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

# भाजपा संगठन को इतनी ताकत दें कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकें : नड्डा

**इंदौर/भोपाल, एजेंसी।**

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता एक उद्देश्य, एक मकसद और एक विचारधारा के साथ समाज और देश को आगे बढ़ाने के कार्य में जुटे हैं। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के पार्टी संगठन को इतना सहयोग करें, इतनी ताकत दें कि वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आंखों से देख सकें।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा इंदौर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने आए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। नड्डा सोमवार की रात विमान से इंदौर पहुंचे थे। इंदौर पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि यहां पधारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताकों का उत्साह यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यों को पूरा करने और जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुटे हुए हैं। आप सभी अपनी मेहनत, लगन और कार्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अपने कार्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनते देखना बड़े गर्व की बात है। इसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में संगठन जहां मध्य प्रदेश में कमल को खिलाने में जुटा है, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी पूरी टीम मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। मेरा आप सभी से आह्वान है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता सरकार और संगठन को और मजबूती देने के लिए कार्य करें, ताकि हम सभी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनता हुआ अपनी आंखों से देख सकें।

सार समाचार

## फोरलेन पर आपस में भिड़ीं दो गाड़ियां, 5 घायल

**बैतूल, एजेंसी।** मध्यप्रदेश के बैतूल–नागपुर फोरलेन (हाईवे-46) पर सड़क पर फैली गिट्टी के चलते एक के बाद एक तीन कारें दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पांच लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कल देर शाम बेंगलुरु से वृंदावन की ओर जा रही एक कार अचानक सापना डेम के पास करीब 20 मीटर तक सड़क पर बिखरी गिट्टी पर फिसल गई। चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कार अनियंत्रित होकर पलटते हुए सड़क से नीचे जा गिरी। कुछ ही देर में पीछे से आ रही दो अन्य कारें भी उसी गिट्टी पर फिसल गईं और आपस में भीषण टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कारों में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। महिलाओं को ज्यादा चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को बाहर निकाला।

## भिण्ड के अटेर में पर्यटन को नया आयाम

**भिण्ड, एजेंसी।** मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में सदियों तक बीहड़ों और दस्यु कथाओं के लिए पहचानी जाने वाली चंबल अब पर्यटन की नई पहचान गढ़ रही है। अटेर किले की तलहटी में बहती चंबल नदी इन दिनों पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रही है। भुरभुरी रेत, खुला आसमान और राजस्थानी ऊंटों की सवारी का नजारा लोगों को गोवा के समुद्र तट जैसा अहसास करा रहा है। इसी क्रम में वन विभाग ने अटेर में चंबल नदी किनारे ऊंट सफारी की शुरुआत की है, जिसमें शुरुआत में स्थानीय लोगों के 11 ऊंट शामिल किए गए हैं।

ऊंट सफारी के लिए दो श्रेणियों में टिकट निर्धारित किए गए हैं। 200 रुपये के टिकट में पर्यटकों को चंबल नदी किनारे रेत पर करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की सवारी कराई जाती है। वहीं 500 रुपये के टिकट में लगभग 10 किलोमीटर का ट्रेक शामिल है।

# मध्य प्रदेश को भोपाल मेट्रो समेत पिछले सप्ताह मिली अनेक सौगात : मुख्यमंत्री यादव

**भोपाल, एजेंसी।**

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीते सप्ताह प्रदेश को कई नई सौगातें मिली हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की विशिष्ट उपस्थिति में न केवल भोपाल में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हुआ, वरन् प्रदेश के पहले भोपाल महानगरीय क्षेत्र (मेट्रोपोलिटन एरिया) का मैप (मानचित्र) भी लांच कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भोपाल मेट्रोपोलिटन एरिया में भोपाल जिले सहित सीमावर्ती 5 जिलों रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और नर्मदापुरम का क्षेत्र शामिल किया गया है। इस एरिया में कुल 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसीलें शामिल की गई हैं। मेट्रोपोलिटन एरिया में लगभग 2524 गांव शामिल होंगे और इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 12,099 वर्ग किलोमीटर रहेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश को दिन-ब-दिन मिल रही नई-नई सौगातों के लिए सभी मंत्रीगण ने मेंजें थप-थपाकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण को बताया कि भोपाल को मेट्रो की सौगात मिली है। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल द्वारा 20 दिसम्बर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में 7 किमी का मेट्रो ट्रेक सुभाष नगर से एम्स तक का है। इसमें कुल 8 स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर इन्दौर और भोपाल अब मेट्रो ट्रेन अल्ट्रा माडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन्दौर में 3.3 किमी के अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन ट्रेक के निर्माण के लिए भी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने इन सभी सौगातों के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को बताया कि प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर चार मेडिकल कॉलेज तैयार किए जाएंगे। इनमें से धार एवं बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का भूमिपूजन मंगलवार, 23 दिसम्बर को धार एवं बैतूल में सम्पन्न होगा। मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा पीपीपी मॉडल पर बनने वाले दो मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नड्डा पूर्वान्ह में धार में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन एवं अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण करने के बाद वहीं से बैतूल रवाना होंगे। नड्डा अपरान्ह में बैतूल में मेडिकल कॉलेज एवं अन्य विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन सौगातों के लिये भी प्रधानमंत्री मोदी एवं केन्द्रीय मंत्री नड्डा का आभार माना।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसम्बर को मध्य प्रदेश आएंगे। गृहमंत्री शाह भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर ग्वालियर एवं रीवा में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री शाह 25 दिसम्बर को ग्वालियर में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री शाह ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक के कामों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करने के साथ-साथ निवेशकों को आशय पत्र/आवंटन आदेश का वितरण भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री यहां एक मेले का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वे रीवा पहुंचेंगे और वहां आयोजित कृषि एवं किसान सम्मेलन में भाग लेंगे।

# तमाम बाधाओं के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर: वडिंग

**चंडीगढ़, एजेंसी।**

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सोमवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल द्वारा जिला परिषद और ब्लॉक समिति के नतीजों को लेकर फैलाये जा रहे झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि 'आप' ने सत्ता का दुरुपयोग किया और चुनावी उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में हेरफेर की गयी , लेकिन फिर भी वह प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं दिखा सकी।

शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह केवल दो जिलों बठिंडा और मुक्तसर तक सीमित रहा, जबकि 10 जिलों में पार्टी पूरी तरह खाली रही।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, राजा वड़िंग ने पार्टी के साथियों दुर्लभ सिद्धू और हरदीप सिंह किंगरा के साथ मिलकर विस्तृत आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पटियाला के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा ने अपने जूनियर स्टाफ को निर्देश देकर 'आप' की साजिश का पर्दाफाश किया था कि किस तरह विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया, ताकि बाद में नामांकन रद्द करने की जरूरत न पड़े।

उन्होंने कहा कि पुलिस और चुनाव अधिकारियों ने वास्तव में शर्मा के दिशानिर्देशों का पालन किया, जो स्पष्ट रूप से 'आप' सरकार द्वारा जारी किये गये थे।

राजा वड़िंग ने इस मौके खुलासा किया कि जहां 'आप' 347 जिला परिषद सीटों में से 220 जीतने का दावा कर रही है, वहीं उसने वास्तव में 'चुनावी प्रक्रिया' के जरिये सिर्फ 136 सीटें जीतीं, और इनमें भी सत्ता के दुरुपयोग के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि 'आप' के 84 अतिरिक्त सीटें जीतने के दावे में से 18 सीटों पर बायकॉट हुआ था, 11 सीटें वरुण शर्मा के इशारे पर निर्विरोध जीती गयीं, पांच सीटों पर कागज फाड़े गये और 32 अन्य सीटों पर नामांकन मनमाने ढंग से रद्द किए गए। उन्होंने बताया कि 'आप' ने 136 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 62, शिरोमणि अकाली दल ने 46, भाजपा ने सात और अन्य ने 11 सीटें जीतीं थीं। इसी तरह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्लॉक समिति के नतीजों पर 'आप' के दावों का भी पर्दाफाश किया।

## मनरेगा पर हमला बर्दाश्त नहीं, जामताड़ा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन

**रांची, एजेंसी।**

झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जामताड़ा में केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा- मनरेगा कांग्रेस की ऐतिहासिक देन है।

यह योजना सोनिया गांधी द्वारा देश के किसानों, मजदूरों और गरीबों को रोज़गार की कानूनी गारंटी देने के लिए लाई गई थी। आज यह करोड़ों गरीब परिवारों की जीवनरेखा है, लेकिन भाजपा इसे कमजोर करने और धीरे-धीरे खत्म करने की साजिश कर रही है। जामताड़ा में कांग्रेस पार्टी का मनरेगा योजना से छेड़छाड़ और उसका नाम बदलने की भाजपा की साजिश के खिलाफ आज जबरदस्त, उग्र और ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। इस आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं युवा साथियों की भारी भागीदारी रही। पूरे क्षेत्र में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ गूंजते नारे यह साफ़ संदेश दे रहे थे कि गरीबों के हक़ से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं डॉ. अंसारी ने कहा कि भाजपा को गरीब, किसान और मजदूर की खुशहाली कभी रास नहीं आई। कभी नाम बदलने का खेल, तो कभी 60:40 जैसे प्रावधान — यह सब गरीबों से उनका संवैधानिक अधिकार छीनने की चाल है।

## 'जनादेश परब' में नड्डा ने किया कांग्रेस पर तीखा हमला

**जांजगीर-चांपा, एजेंसी।** केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को जांजगीर पुलिस लाइन में आयोजित 'जनादेश परब' कार्यक्रम में जय सतनाम के उद्घोष के साथ आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और इसे जनविश्वास की जीत बताया।

नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो संकल्प लिए थे, उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश भय, भ्रष्टाचार और समझौतावादी नीतियों से जूझ रहा था। जनता ने उस व्यवस्था को बदलते हुए प्रदेश में भाजपा को अवसर दिया, जिसका परिणाम आज विकास के रूप में सामने है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गांव, गरीब और श्रमिक वर्ग को केंद्र में रखकर कार्य किया है।

# स्वास्थ्य शिविर सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल है : डेका

**रायपुर, एजेंसी।**

आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में आयोजित पाँच दिवसीय निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप के समापन अवसर पर सोमवार को राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि यह आयोजन केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की जीवंत मिसाल है। ऐसे शिविर समाज के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने का माध्यम बनते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए आज भी बेहतर इलाज एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरीब, वंचित और आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। उन्होंने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए शिविर के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ का संकल्प केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह शिविर उस दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।

राज्यपाल डेका ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस शिविर में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 42 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों के 55 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवाएँ प्रदान कीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जाँच, आधुनिक कैंसर स्क्रीनिंग, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत सुविधाओं का आम नागरिकों तक पहुँचना वास्तव में सराहनीय है। जयपुर फुट और कृत्रिम अंगों जैसी सेवाओं ने दिव्यांगजनों के जीवन में नई आशा और आत्मविश्वास का संचार किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समावेश हमारे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सुंदर समन्वय को दर्शाता है। सभी चिकित्सा पद्धतियों किए जा रहे उपचार ने इस शिविर को और अधिक प्रभावी बना दिया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया है।

# वीबी जी-राम जी कानून की जगह पुरानी मनरेगा को दोबारा लागू किया जाए: बादल

**अमृतसर, एजेंसी।**

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण ) ( वीबी जी-राम जी) कानून की जगह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) मनरेगा को दोबारा शुरू करने की मांग की है।

यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मनरेगा की जगह लागू होने वाले नये कानून कानून को रद्द करने के लिए तर्क देते हुए अकाली दल अध्यक्ष श्री बादल ने रोजगार गारंटी योजना के नाम को बदलने और इसकी लागत का 40 फीसदी वहन करने के लिए राज्यों को बाध्य करने के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा, पहले इस योजना का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर था, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद करवाया था, इस पर राजनीति करना और इसका नाम बदलना कतई सही नहीं है। बादल ने केंद्र सरकार के इस फैसले की निंदा की कि नयी योजना में केंद्र और राज्य का योगदान 60 अनुपात 40 है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की तरह आर्थिक गड़बड़ी या धन का दुरुपयोग करने वाले राज्य इसे लागू नही कर पाएंगे, जिससे गरीबों और वंचितों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस और मौजूदा आम आदमी पार्टी दोनों सरकारों ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा, इसी कारण आप सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई सहित विभिन्न योजनाओं में अपना हिस्सा नहीं डाल पा रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों तक चिकित्सा सेवाएं नहीं पहुंच पां रही हैं।

## महिलाओं का सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता :भूरिया

**भोपाल, एजेंसी।** मध्यप्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुश्री भूरिया ने आज यहां मंत्रालय में अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक में कहा है कि बाल विवाह रोकने के सार्थक प्रयास के तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी विद्यार्थियों को समाज की कुरीतियों को दूर करने और रोकने के लिये जागरूक किया जाये। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए तथा जमीनी स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं आदिम जाति विभाग के संयुक्त प्रयास से कामकाजी महिला हॉस्टल की प्रदेश के हर जिले में स्थापना की जाये, ताकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और बेहतर किया जा सके।

# हर परिवार को 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज देने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की जाएगी: मान

**संगरूर, एजेंसी।**

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करेगी, जिससे राज्य के 65 लाख परिवारों के लिए अच्छी हेल्थकेयर के दरवाज़े खुलेंगे। इस योजना के तहत वह पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। इसी तरह, पंजाब सरकार अगले बजट सत्र में जनता की भलाई के लिए कई और जन-हितैषी योजनाएं शुरू करेगी।

मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, " पंजाब सरकार लोगों की सुविधा के लिए शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण इलाकों के बड़े विकास पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए पहले ही कई परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर, स्ट्रीट लाइट, सीवेज की समस्या या दूसरी सभी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा, " पिछले चार सालों में पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है क्योंकि पंजाब सरकार ने कभी भी फंड की कमी की शिकायत नहीं की।

मान ने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्होंने राज्य को कर्ज के जाल में फंसा दिया था, उनकी सरकार कर्ज चुका रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को बेल आउट किया है, चीनी मिलों, मार्कफेड और दूसरों के लोन चुकाए हैं। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार कई पुराने कर्जों को चुका रही है ताकि पिछली देनदारियां चुकाई जा सकें, बिना किसी नए विकास प्रोजेक्ट को रोके। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नाम बदलने से शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। "नाम बदलने से गरीबों का पेट नहीं भरता, बल्कि दिहाड़ी मज़दूरों को सिर्फ़ इस बात की चिंता होती है कि उन्हें काम मिले, ताकि वे अपने परिवारों का पेट भर सकें। जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया या जब सराय काले खान स्टेशन का नाम दीन दयाल उपाध्याय नगर किया गया, तब शायद ही कोई बदलाव देखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुख की बात है कि नाम बदलने के बाद भी इन शहरों में सफ़ाई में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हम सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए कि सत्ता में बैठे लोगों ने अभी तक देश का नाम नहीं बदला है।

## कुएं के विवाद में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग सहित छह गंभीर

**बैतूल, एजेंसी।** मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम मधनी आमढाना में पुश्तैनी कुएं के उपयोग को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। चाचा और भतीजे के परिवारों के बीच हुए इस संघर्ष में 70 वर्षीय बुजुर्ग सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग की हालत नाजुक बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कुएं को बंद करने और उसके उपयोग को लेकर शनिवार से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। मामला बढ़ने पर एक पक्ष द्वारा बोरदेही थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि शिकायत कर थाने से लौटते समय रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 10 से 15 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी, डंडे, रॉड और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस हमले में किशन अमरूते (70) गंभीर रूप से घायल हो गए।

# कहा, राज्य के बच्चे अब उच्चस्तरीय कोचिंग सुविधा यहीं रांची में प्राप्त करेंगे

# हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर युवा तक अवसर की पहुंच: हेमन्त

**रांची, एजेंसी।**

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी स्थित दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग(जी) एवं मेडिकल (नीट) कोचिंग संस्थान का विधिवत उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने संस्थान परिसर का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों से संवाद कर उनके उत्साह और मनोबल को बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की नई पीढ़ी को अपने सपनों को साकार करने के लिए अब राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सोरेन ने कहा, राज्य के बच्चे अब उच्चस्तरीय कोचिंग सुविधा यहीं रांची में प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बनेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को साझा करने का आग्रह किया, जिससे झारखंड की विविधता और एकता को और बल मिले।

सोरेन ने कहा कि उन अभ्यर्थियों को पुनः अवसर प्रदान किया जाए, जो एबिलिटी टेस्ट में मामूली अंतर से पीछे रह गए थे। उन्होंने कहा कि कई बार परिस्थितिजन्य कारणों से विद्यार्थी अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें दोबारा अवसर देना एक न्यायोचित और प्रेरणादायक कदम होगा। इससे न केवल अधिक विद्यार्थियों को मंच मिलेगा, बल्कि राज्य की प्रतिभा का दायरा भी विस्तृत होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संस्था में खेल-कूद की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा के साथ-साथ खेल भी छात्रों में अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धी सोच का विकास करता है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों के बीच आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना का संचार करें, ताकि ये युवा आगे चलकर न केवल राज्य, बल्कि देश का नाम भी रोशन करें।

झारखंड सरकार शिक्षा को राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख आधार मानते हुए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन है। इसी सोच के अनुरूप राज्य में विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ लाखों विद्यार्थियों तक पहुँच रहा है।

सोरेन ने बताया कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से किशोरियों को न केवल शिक्षा का अवसर प्राप्त हो रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरणा मिल रही है। इसी प्रकार प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक संबल मिल रहा है।

# मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों से व्यवस्थित तरीके से मनरेगा को कमजोर किया है: पटेल

**रांची, एजेंसी।**

झारखंड कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य कमलेश्वर पटेल ने कहा कि एक तरफ भाजपा ने मनरेगा कानून को बदल दिया दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके वर्षों तक सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश की गई।

दोनों घटनाओं में भाजपा ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है।

श्री पटेल ने कहा मोदी सरकार ने लगातार पिछले 11 वर्षों से साजिशन व्यवस्थित तरीके से मनरेगा को कमजोर किया, पिछले 5 वर्षों में मनरेगा 50-55 दिन का रोजगार देने तक सिमट गया।मनरेगा सिर्फ महात्मा गांधी का नाम बदलने का मामला नहीं बल्कि उस अधिकार को खत्म किया गया जिसे कांग्रेस ने कानून के रूप में सुनिश्चित किया था। मनरेगा के लिए तैयार मसौदे को जिस स्थायी समिति के पास भेजा गया उसके अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह थे।

श्री पटेल ने कहा मनरेगा से प्रतिवर्ष 5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला यह उनके आत्मसम्मान का अधिकार था, यह कानून संविधान के अनुच्छेद 21 से मिलने वाले अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। मनरेगा में कुल खर्च का 90% केंद्र सरकार देती थी नए कानून में केंद्र राज्य का अनुपात 60:40 कर दिया गया है, मोदी सरकार राज्यों पर 50000 करोड़ से अधिक का बोझ डालने वाली है जो राज्यों की आर्थिक नींव को हिला देगा।

# श्रीलंका पर एक और बड़ी जीत हासिल करने उतरेगा भारत, फील्डिंग पर होगी निगाह

**भारतीय टीम ने पिछले महीने विश्व कप जीतने के बाद बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया।**

**विशाखापत्तनम, एजेंसी।** पहले मैच में बड़ी जीत हासिल करने से उत्साहित भारतीय महिला क्रिकेट टीम जब श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मैदान पर उतरेगी तो वह फील्डिंग के स्तर को बेहतर करके अपना विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी।

भारतीय टीम ने पिछले महीने विश्व कप जीतने के बाद बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया और श्रीलंका को आठ विकेट से हराया। भारतीय टीम ने श्रीलंका को केवल छह विकेट पर 121 रन पर रोक दिया था लेकिन इस बीच उसकी फील्डिंग अपेक्षानुरूप नहीं रही और उसने कुछ कैच छोड़े।

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, ''हम अपनी फील्डिंग पर काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हम बार-बार कैच छोड़ रहे हैं। मैदान गीला था, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अगले मैच में हम बेहतर रणनीति के साथ उतरेंगे।''

विश्व कप की सफलता के बाद भारतीय टीम को छह सप्ताह का ब्रेक मिला। इसके बाद भारतीय टीम ने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक सप्ताह के शिविर में भाग लिया था।

फील्डिंग में थोड़ी बहुत कमी आना लगभग अपेक्षित था और कप्तान को लगता है कि टीम बहुत जल्द लय में आ जाएगी। हरमनप्रीत ने कहा, ''हम एक महीने बाद खेल रहे हैं। हम खुद को बेवजह चुनौती नहीं देना चाहते। हम बस टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं।''

कागजों पर भी भारतीय टीम मजबूत नजर आती है। उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काफी मजबूत हैं। सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रही जेमिमा रोड्रिग्स ने विश्व कप के अपने शानदार प्रदर्शन को यहां भी जारी रखा। भारत के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू 20 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा का टीम में शामिल होना रहा, जिन्हें हाल ही में महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में नजरअंदाज कर दिया गया था। वैष्णवी को भले की कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने चार ओवर में केवल 16 रन दिए और एक भी चौका नहीं लगने दिया। शैफाली वर्मा के लिए यह श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है तथा वह उस प्रारूप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी जो उनकी बल्लेबाजी शैली के अनुरूप है।

टीम इस प्रकार हैं: भारतः हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा।

श्रीलंकाः चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेववंडी, मल्की मदारा।

मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा।

# हॉकी चले फुटबाल की चाल!

**राजेंद्र सजवान**

'भारतीय हॉकी आज जहाँ खड़ी हैं वहां से गहरी खाई ज्यादा दूर नहीं है । यदि समय रहते प्रयास नहीं किए गए तो हॉकी की हालत भारतीय फुटबाल जैसी हो सकती हैं', एक पूर्व ओलम्पिक चैंपियन हॉकी खिलाड़ी की इस प्रतिक्रिया पर कुछ हॉकी प्रेमी नाक भौं सिकोड सकते हैं तो कुछ एक बुरा भला भी कह सकते हैं। लेकिन हॉकी की गहरी समझ रखने वाले मानते हैं कि भारतीय हॉकी सही दिशा में नहीं बढ़ रही । ठीक वैसे ही जैसे कि फुटबाल लगातार नीचे लुढ़क रही हैं और फीफा रैंकिंग में 150 वें स्थान के आस पास पहुँच गई है ।

यूँ तो हॉकी और फुटबाल की कोई तुलना नहीं हो सकती । एक पूरी दुनिया का खेल हैं तो हॉकी मात्र दस बारह देश ही गंभीरता के खेलते हैं, जिसमें हमारी स्थिति लगातार ख़राब हो रही हैं । चूंकि हॉकी हमारा अपना खेल है और हम कभी इस खेल के बेताज बादशाह रहे हैं इसलिए लगातार गिरती साख चिंता का विषय बनी हैं । यह सही है कि भारतीय हॉकी ने आठ ओलिंपिक स्वर्ण जीते हैं और एक बार विश्व विजेता भी रहे हैं। लगातार दो ओलिंपिक काँस्य जीत कर उम्मीद जरूर जगाई है लेकिन इसे भारतीय हॉकी की वापसी नहीं कह सकते क्योंकि विश्व रैंकिंग में सातवें आठवें स्थान पर हैं ।

जहाँ तक फुटबाल की बात है तो इस खेल में अर्जित मान- सम्मान पूरी तरह धुल चुका है । जिस खेल में विश्व स्तरीय पहचान थी और कभी यूरोप और लेटिन अमेरिका के देशों को टक्कर देते थे उसमें मैच दर मैच पिछड़ रहे हैं । इसलिए क्योंकि फुटबाल फेडरेशन और उसकी सदस्य इकाइयां भ्रष्टाचार की शिकार हैं और आईएसएल और आई लीग पर संकट मंडरा रहा है । लेकिन सबसे बड़ा नुक्सान देश भर में खेले जाने वाले जाने माने टूर्नामेंट के बंद होने से पहुंचा है । बेशक़, इस दयनीय स्थिति का बड़ा कारण आईएसएल और आई लीग जैसे घटिया आयोजन हैं । कुछ इसी प्रकार की स्थिति का सामना हॉकी को भी करना पड़ रहा है । हॉकी के कई बड़े आयोजन ठप्प होने की कगार पर हैं । यह खेल चंद प्रदेशों का खेल बन कर रहा गया है और आम हॉकी प्रेमी की पकड़ और पहुँच से लगातार दूर हो रहा है । जो थोड़े बहुत आयोजन होते हैं उनमें दर्शक खोजे नहीं मिलते 1 ठीक वैसे ही जैसे फुटबाल के अधिकांश मैच खाली पड़े स्टेडियमों में खेले जाते हैं 1 ऐसे में डर है कि कहीं भारतीय हॉकी भी फुटबाल की तरह फुस्स ना हो जाए1

# न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत से श्रृंखला अपने नाम की

माउंट माउंगा नुई (न्यूजीलैंड)। तेज गेंदबाज जैकब डफी ने 42 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवे और अंतिम दिन सोमवार को यहां 323 रन से बड़ी जीत हासिल करके तीन मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की।

वेस्टइंडीज के सामने 462 रन का मुश्किल लक्ष्य था। उसने सुबह अपनी दूसरी पारी बिना किसी नुकसान के 43 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसकी पूरी टीम 138 रन बनाकर आउट हो गई। उसके केवल चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें ब्रैंडन किंग ने सर्वाधिक 67 रन बनाए।

न्यूजीलैंड की तरफ से डफी के अलावा अयाज पटेल ने 23 रन देकर तीन विकेट लिए। ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र ने एक-एक विकेट हासिल किया। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 575 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 420 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 306 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। उसकी तरफ से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने दोनों पारियों में शतक लगाने का कारनामा किया।

डफी ने एक कैलेंडर वर्ष में 80 विकेट लेने के रिचर्ड हैडली के न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने इस श्रृंखला में 15.4 के औसत से 23 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने तीन बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा भी किया।

# वर्ष 2025 में भारतीय एथलेटिक्सः नीरज ने 90 मीटर का जादुई आंकड़ा छुआ

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा फॉर्म में उतार चढ़ाव के बावजूद 90 मीटर तक भाला फेंकने के जादुई आंकड़े को छूने में आखिरकार सफल रहे लेकिन इस बीच वर्ष 2025 में भारतीय एथलेटिक्स को डोपिंग का डंक भी डसता रहा।

चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक में मानक माने जाने वाले 90 मीटर की दूरी हासिल की लेकिन इसी वर्ष तोक्यो में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पदक जीतने में नाकाम रहने से उन्हें निराशा भी हाथ लगी।

इस प्रतियोगिता में युवा सचिन यादव ने चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया और इस तरह से भाला फेंक में विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की।

लेकिन डोपिंग का खतरा कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कई शीर्ष भारतीय खिलाड़ी इसकी चपेट में आ गए। इनमें ओलंपियन भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह और एशियाई खेलों की पूर्व पदक विजेता चक्का फेंक की खिलाड़ी सीमा पुनिया भी शामिल हैं। अपनी तरह के पहले मामले में एक एथलीट और उसके कोच की जोड़ी को डोपिंग के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि दो नाबालिग एथलीट भी डोपिंग में पकड़े गए। इन सबके बीच सकारात्मक पहलू यह रहा कि भारत ने दो विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर प्रतियोगिताओं की मेजबानी की। इनमें से एक में चोपड़ा ने मेजबानी की और जीत हासिल की। भारत ने इसके अलावा 2031 में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप सहित कुछ प्रमुख महाद्वीपीय और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए बोली लगाई है।

भारतीय खेलों के नायक चोपड़ा इस साल हिमाचल प्रदेश के एक निजी रिसॉर्ट में टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के साथ परिणय सूत्र में बंधे। इस समारोह में कुछ करीबी रिश्तेदार और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। लोगों को इसके बारे में तभी पता चला जब चोपड़ा ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरें पोस्ट कीं। इसके कुछ महीनों बाद चोपड़ा ने अपना भाला 90.23 मीटर तक फेंका और ऐसा करने वाले एशिया के तीसरे और कुल मिलाकर 25वें खिलाड़ी बन गए। चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग, गोल्डन स्पाइक मीट और एनसी क्लासिक के रूप में इस साल तीन बड़े खिताब जीते। उन्होंने घरेलू दर्शकों और परिवार के सदस्यों के सामने एनसी क्लासिक के रूप में विश्व स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अपना सपना साकार किया।

# वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में हार के बाद संन्यास लेने पर विचार किया थाः रोहित

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि 2023 में खेले गए वनडे विश्व के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद उन्होंने संन्यास लेने पर विचार किया था क्योंकि उन्हें लगा कि ''इस खेल ने उनसे सब कुछ छीन लिया है।''

भारत ने घरेलू मैदान पर खेले गए इस वनडे विश्व कप में रोहित की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया था तथा लगातार नौ मैच जीत कर फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन इस महत्वपूर्ण मैच में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने शतक लगाया था जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ।

रोहित ने मास्टर्स यूनियन के एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ''वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद मैं पूरी तरह से निराश हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यह खेल नहीं खेलना चाहता क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है।''

उन्होंने कहा, ''मुझे इससे उबरने में थोड़ा समय लगा। मैं खुद को बार-बार याद दिलाता रहा कि यही वह चीज है जिससे मुझे वास्तव में प्यार है। यह चीज मेरे पास है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। धीरे-धीरे मैं इससे उबर गया। मैंने अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस हासिल की और फिर से मैदान पर सक्रिय हो गया।''

## बिजनेस

**जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा कॉरिडोर**

**लखनऊ।** योगी सरकार ने औद्योगिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिए जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1,246 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया है।

**भारत में 2025 में आईटी भर्तियों में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी: रिपोर्ट**

**मुंबई, एजेंसी।** भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में 2025 में सुधार के संकेत देखने को मिले हैं और इस दौरान कुल रोजगार मांग बढ़कर 18 लाख भूमिकाओं तक पहुंच गई। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है।

# श्रीराम फाइनेंस में एमयूएफजी बैंक 39,618 करोड़ रुपये का निवेश करेगा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** वित्तीय सेवा कंपनी श्रीराम फाइनेंस लि. के निदेशक मंडल ने सोमवार को जापान के एमयूएफजी बैंक लि. के साथ पक्के समझौते को मंजूरी दे दी। इसके तहत एमयूएफजी बैंक, कंपनी में 39,618 करोड़ रुपये (4.4 अरब डॉलर) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगा।

यह बिक्री तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर जारी कर की जाएगी। यह भारत में किसी वित्तीय सेवा कंपनी में अबतक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है।

कंपनी के कार्यकारी वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर ने संवाददाताओं को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ''श्रीराम फाइनेंस के निदेशक मंडल ने एमयूएफजी बैंक लि. के साथ पक्के

समझौते को मंजूरी दे दी। इसके तहत जापान की मित्शुबिसी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप की इकाई एमयूएफजी बैंक कंपनी में 39,618 करोड़ रुपये निवेश के जरिये 20 प्रतिशत हिस्सेदारी ले रहा है।''

एमयूएफजी बैंक द्वारा प्रस्तावित यह अल्पांश निवेश शेयरधारकों, नियामकीय मंजूरियों तथा अन्य संबंधित शर्तों के अधीन है। इस सौदे के बाद प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी 20.3 प्रतिशत, एमयूएफजी बैंक की 20 प्रतिशत तथा अन्य सार्वजनिक शेयरधारकों के पास 59.7 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

उन्होंने कहा, ''यह सहयोग एसएफएल की सशक्त घरेलू फ्रेंचाइज और व्यापक वितरण नेटवर्क को एमयूएफजी बैंक की वैश्विक विशेषज्ञता और वित्तीय शक्ति के साथ जोड़ता है। इस पूंजी निवेश से एसएफएल की पूंजी पर्याप्तता में उल्लेखनीय सुधार होगा। बही-खाता मजबूत होगा और दीर्घकालिक विकास के लिए पूंजी उपलब्ध होगी।''

साथ ही, तकनीक, नवोन्मेष और ग्राहक जुड़ाव बेहतर होने की उम्मीद है। इससे कम लागत वाली देनदारियों तक पहुंच बेहतर होगी और एसएफएल की क्रेडिट रेटिंग मजबूत होने की संभावना है। इसके साथ कंपनी संचालन और परिचालन प्रक्रियाएं वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप होंगी।

रेवांकर ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''हम सालाना 100 से 150 नई शाखाएं खोलेंगे और 3,000 से 5,000 लोगों को नियुक्त करेंगे।''

श्रीराम समूह की प्रमुख कंपनी में वर्तमान में 78,800 कर्मचारी हैं जबकि शाखाओं की संख्या 3,225 है। इस मौके पर एमएफयूजी के वैश्विक वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय समूह के समूह प्रमुख यासुशी इतागाकी ने कहा, ''यह निवेश भारत के गतिशील वित्तीय सेवा क्षेत्र में एमयूएफजी बैंक के भरोसे को दर्शाता है...।'' एमयूएफजी बैंक की मूल कंपनी, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (एमयूएफजी) ने अबतक भारत में 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और लगभग 5,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। श्रीराम फाइनेंस में किया गया यह निवेश एमयूएफजी का भारत में अबतक का सबसे बड़ा निवेश होगा।

रेवांकर ने कहा, ''यह लेनदेन हमारी विकास यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। एमयूएफजी दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक है। एक प्रमुख निवेशक के रूप में एमयूएफजी का प्रवेश भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र और उसमें हमारी नेतृत्वकारी भूमिका पर वैश्विक विश्वास को मजबूत बनाता है।''

# सेंसेक्स 638 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,000 अंक के पार

**मुंबई, एजेंसी।** स्थानीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला सोमवार को दूसरे कारोबारी सत्र में जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स 638 अंक चढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी 26,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी निवेश तथा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में और कटौती की उम्मीद से निवेशकों की धारणा सकारात्मक रहने से बाजार बढ़त में रहा।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 638.12 अंक यानी 0.75 प्रतिशत चढ़कर 85,567.48 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 671.97 अंक तक चढ़ गया था।

पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 206 अंक यानी 0.79 प्रतिशत चढ़कर 26,000 अंक के पार 26,172.40 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से ट्रेंट में सर्वाधिक 3.56 प्रतिशत की तेजी

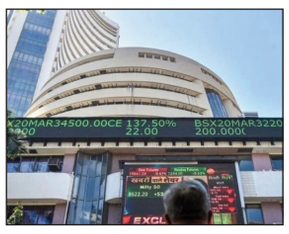

रही। इसके अलावा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, भारती एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स, रिलायंस और मारुति प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ, भारतीय स्टेट बैंक सर्वाधिक 0.6 प्रतिशत नुकसान में रहा। इसके अलावा, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और टाइटन भी नुकसान में रहे।

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''मजबूत नकदी और वैश्विक संकेतों के समर्थन से भारतीय बाजार ने साल के अंत की तेजी को बरकरार रखा है। इसका कारण 2026 में फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दर में और कटौती की उम्मीद है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुद्ध लिवाली की, जिससे सकारात्मक माहौल और मजबूत हुआ। इसमें आईटी और धातु क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हुआ।''

छोटी कंपनियों से जुड़ा बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 1.12 प्रतिशत चढ़ा, जबकि मझोली कंपनियों का मिडकैप 0.86 प्रतिशत मजबूत हुआ।

बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में 2,796 के शेयर लाभ में, जबकि 1,514 शेयर नुकसान में रहे। 191 शेयर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "अमेरिकी डॉलर-रुपया विनिमय दर में स्थिरता और पिछले कुछ सत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की घरेलू शेयरों की शुद्ध लिवाली के साथ चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है।

# सोना 1.38 लाख रुपये के नए शिखर पर, चांदी का भी नया रिकॉर्ड

**नई दिल्ली, एजेंसी।** वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 1,685 रुपये की बढ़त के साथ 1,38,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। राजधानी में चांदी की कीमतें भी 10,400 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 2,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गईं।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ''सोने और चांदी के सोमवार को एक और नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से सर्राफा में तेजी का दौर जारी रहा।'' अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना हाजिर 80.85 डॉलर यानी 1.86 प्रतिशत बढ़कर 4,420.35 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

गांधी ने कहा, ''चांदी और सोने में निवेशकों की रुचि काफी बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें कम हो रही हैं, राजकोषीय चिंताएं बढ़ रही हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था अधिक अनिश्चित होती जा रही है।'' उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षित-संपत्ति की ओर बदलाव आया है। इसके अलावा, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षित निवेश विकल्प की मांग भी बढ़ गई है। विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी 2.31 डॉलर या 3.44 प्रतिशत बढ़कर 69.45 डॉलर प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कोटक म्यूचुअल फंड के कोष प्रबंधक, सतीश डोंडापति ने कहा, ''चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जो बढ़ती निवेश मांग के साथ-साथ मजबूत औद्योगिक मांग को दर्शाती है।''

# कोयला क्षेत्र 2026 में बड़े बदलाव के लिए तैयार, सीआईएल की इकाइयां होंगी सूचीबद्ध

**नई दिल्ली, एजेंसी।** सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की दो अनुषंगी कंपनियों के बाजार में सूचीबद्ध होने से लेकर महत्वाकांक्षी कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में तेजी तक, कोयला क्षेत्र 2026 में बड़े बदलाव के लिए तैयार है।

महत्वाकांक्षी खनन सुधारों और अहम खनिजों की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ ही 2026 में हरित ऊर्जा की रफ्तार भी तेज रहेगी और इसे सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा।

भारत अपने महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत 2047' लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है और केंद्र सरकार राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू कर रही है।

इन बदलावों का लक्ष्य जटिल मंजूरी प्रक्रियाओं, कमजोर माल रवानगी व्यवस्था और सुरक्षा

प्रोटोकॉल जैसी प्रमुख समस्याओं को दूर करना है, ताकि एक मजबूत और आत्मनिर्भर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके।

ये पहल स्वच्छ ऊर्जा की स्वीकार्यता में तेजी लाएंगी, आयात पर निर्भरता कम करेंगी और 2047 तक 30,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी।

कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ''मंत्रालय ऊर्जा सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए कई सुधारों पर काम कर रहा है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। इन सुधारों में आमतौर पर खनन सुधार और मंजूरी प्रक्रिया से जुड़े सुधार शामिल होंगे। रवानगी और सुरक्षा में भी सुधार होंगे।''

स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक साहसिक कदम के तहत आने वाले वर्ष में देश का खनन क्षेत्र तकनीकी क्रांति से गुजरेगा। कोयला कंपनियां उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित खनन के तरीकों को अपना सकती हैं।

अधिकारी ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को 2026 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) भी सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारी कर रही है।

आने वाले वर्ष में सरकार देश की बढ़ती ऊर्जा और रासायनिक जरूरतों को पूरा करने और आयात घटाने के लिए कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण बढ़ा सकती है।

# रहमान डकैत के हुकस्टेप को शिल्पा शेट्टी ने किया कॉपी, 'धुरंधर' को कहा 'देशभक्ति की कहानी



**मुंबई।** आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' अपने नाम की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि फिल्म का बजट लगभग 280 करोड़ रुपए बताया गया है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी फिल्म की तारीफ की और इसके हुक-स्टेप को भी करके दिखाया।

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर अक्षय खन्ना की तरह डांस करते हुए वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो बिल्कुल 'रहमान डकैत' के हुक-स्टेप को कॉपी कर रही हैं। उन्होंने कैप्शन में फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'फैन तो मिला नहीं, लेकिन मैं फैन हो गई हूं, तो यह ट्रेंड करना बनता था। रणवीर सिंह, आपका टाइम आ गया है। अंडरप्लेड लेकिन फिर भी कैरेक्टर में एकदम फिट। अक्षय खन्ना का ओजी ओरा मैक्स। आर. माधवन, आपसे बेहतर इस रोल को कोई नहीं कर सकता था। संजय दत्त, आप हमेशा की तरह रॉकस्टार लगे।

'उन्होंने आगे लिखा, 'कास्टिंग टीम ने फिल्म की शानदार कास्टिंग की और इसका क्रेडिट मुकेश छाबड़ा को जाता है, जिन्होंने ये सब एक साथ किया। बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक शानदार है, और ये गाने मेरी प्लेलिस्ट में शामिल हो गए हैं।

'फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर को लेकर शिल्पा ने कहा, 'आप सच में एक विजनरी हैं। लंबे समय बाद देखी गई देशभक्ति वाली फिल्मों में से एक आपने बनाई है। 'धुरंधर' की पूरी टीम को सलाम।'

दूसरी तरफ बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास भी 'धुरंधर' के गाने पर झूमते दिखाई दिए थे। वहीं, दूसरे स्टार्स भी फिल्म की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। आम से लेकर खास तक सभी फिल्म को देखकर ओवरऑल एक्सपीरियंस शानदार बता रहे हैं।अगर 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखें तो इसमें हर दिन इजाफा होता दिख रहा है। फिल्म रिलीज होने के 17 दिनों के बाद भारत में नेट कलेक्शन 555 करोड़ रुपए के पार हो गया। जबकि, फिल्म का वर्ल्डवाइड नेट कलेक्शन 850 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंचने वाला है।

## 'कार एक्सीडेंट ने समझाई जिंदगी की अहमियत'

# मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हादसे को लेकर बोलीं डोनल बिष्ट

**मुंबई।** टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्री डोनल बिष्ट के साथ एक गंभीर हादसा हुआ। इस कार एक्सीडेंट ने डोनल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस हादसे को लेकर आईएएनएस से बात करते हुए डोनल ने अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे ऐसे पल इंसान को जिंदगी की अहमियत समझा देते हैं।

आईएएनएस से बातचीत में डोनल बिष्ट ने बताया कि यह हादसा तब हुआ, जब वह शूटिंग पर जा रही थीं। उन्होंने कहा, "यह हादसा 19 दिसंबर को मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ था। मैं रोज की तरह अपने काम पर जा रही थी। ड्राइवर ने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हादसा हो गया।"

अभिनेत्री ने कहा, "टक्कर के बाद कार और ट्रक आपस में फंस गए थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि दोनों गाड़ियां करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटती चली गईं। यह पूरा वाकया कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन उन पलों में डर और घबराहट चरम पर थी। आखिरकार ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, जिससे दोनों वाहन अलग हो पाए।"

डोनल ने कहा कि अगर समय पर ब्रेक नहीं लगते, तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते थे।उन्होंने कहा, "हादसे के बाद हम काफी देर तक सदमे में रहे। उस समय किसी को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। भगवान का शुक्र है कि हादसे में सभी सुरक्षित रहे और किसी को जानलेवा चोट नहीं आई। हादसे के बाद शरीर से ज्यादा मन पर असर पड़ा और डर काफी समय तक बना रहा।"

डोनल ने बताया कि एक्सीडेंट के बावजूद उन्होंने अपने काम के कमिटमेंट पूरे किए। उन्होंने कहा, "प्रोफेशनल जिंदगी में कई बार इंसान को अपनी निजी भावनाओं को अलग रखकर काम करना पड़ता है। शूटिंग के दौरान मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 'शो मस्ट गो ऑन' की सोच बहुत गहरी है।"उन्होंने कहा, "जब काम खत्म हुआ और मुझे खुद के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला, तब एहसास हुआ कि वह हादसा कितना डरावना था। उस समय जिंदगी की अहमियत समझ आई। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इस अनुभव से मैंने यह सीख ली कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, जिंदगी रुकती नहीं है और इंसान को आगे बढ़ते रहना पड़ता है।'

# कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने दिल्ली में बढ़ाया फिल्म 'तू मेरी, मैं तेरा' का प्रमोशनल उत्साह

दिल्ली पहुंची 'तू मेरी, मैं तेरा' की जोड़ी, कार्तिक आर्यन–अनन्या पांडे ने की मीडिया से बातचीतइंपीरियल होटल में 'तू मेरी, मैं तेरा' का प्रमोशन, कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री ने बटोरी सुर्खियांबॉलीवुड के चर्चित सितारे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी आगामी फिल्म "तू मेरी, मैं तेरा — मैं तेरा, तू मेरी" के प्रमोशनल सिलसिले में राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस अवसर पर दोनों कलाकारों ने इंपीरियल होटल, नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत की और फिल्म से जुड़े कई रोचक पहलुओं को साझा किया।

प्रेस इंटरेक्शन के दौरान कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने फिल्म की कहानी, अपने-अपने किरदारों और शूटिंग के अनुभवों पर खुलकर बात की। दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

कार्तिक आर्यन ने कहा कि यह फिल्म एक नई तरह की रोमांटिक कहानी पेश करेगी, जो आज की पीढ़ी से गहराई से जुड़ती है। वहीं अनन्या पांडे ने फिल्म को अपने करियर का एक खास प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि दर्शकों को इसमें भावनाओं, प्यार और मनोरंजन का भरपूर मेल देखने को मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान दोनों सितारों ने फोटोग्राफर्स के लिए पोज़ दिए और फैन्स के उत्साह का भी जवाब दिया। फिल्म "तू मेरी, मैं तेरा — मैं तेरा, तू मेरी" को लेकर राजधानी में आयोजित यह कार्यक्रम चर्चा का केंद्र बना रहा और सोशल मीडिया पर भी इसकी झलकियां तेजी से वायरल हो रही हैं।

## विदेश

### रूसी राजदूत ने बांग्लादेश को भारत के साथ तनाव दूर करने की दी सलाह

**नई दिल्ली।** बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध भी ताक पर हैं। बीते कुछ समय में बांग्लादेश में भारत के दूतावास को भी निशाना बनाने और भारत विरोधी नारा देने की कई घटनाएं सामने आई।

### जापानी सांसदों के ताइवान दौरे पर भड़का बीजिंग, आपत्ति कराई दर्ज

**बीजिंग।** चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि जापान के सांसदों का वर्तमान ताइवान दौरा भड़काऊ और उकसावे की नीति का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग ने जापानी पक्ष से इसकी आधिकारिक शिकायत कर दी है।

# बांग्लादेश भारत के बिना नहीं रह सकता है, हमारे ऊपर वह निर्भर है : पूर्व राजनयिक महेश कुमार सचदेव

**नई दिल्ली।** बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, उसकी वजह से भारत में भी लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से बांग्लादेश में हिंसा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासतौर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू युवक को जिस बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा गया और फिर उसके शव को आग के हवाले किया गया, इसकी खूब आलोचना हो रही है। इस बीच पूर्व डिप्लोमैट महेश कुमार सचदेव ने बांग्लादेश के हालात को लेकर आईएएनएस के साथ खास बातचीत की है।भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को लेकर पूर्व राजनयिक महेश कुमार सचदेव ने कहा, '12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले कुछ समय के लिए तनाव हो सकता है। लेकिन लंबे समय में, अच्छे पड़ोस और ठोस आर्थिक तालमेल का लॉजिक दोनों देशों के रिश्तों को बनाए रखेगा।'

उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ता ऐतिहासिक है। दोनों ही दक्षिणी एशिया के इलाके का हिस्सा हैं, और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरी दोस्ती है। लेकिन अभी कुछ चुनौतियां हैं। मैं इसे इसी नजरिए से देखता हूं, और मेरे हिसाब से, ये चुनौतियां कुछ समय के लिए हैं, और ये राजनीतिक वजहों से हैं। उम्मीद है कि ये जल्द ही हल हो जाएंगी।'

दोनों देशों के बीच इस तनाव के असर को लेकर महेश कुमार सचदेव ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि लंबे समय में कोई बड़ी समस्या होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में साफ है कि यह तनाव है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। शेख हसीना पहले भारत को समर्थन करती थीं और वह लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। उनके निर्वासन को लेकर ये हुआ है, क्योंकि वह भारत में हैं। और उनके विरोधी इस समय सत्ता में हैं, या सत्ता के करीब हैं। क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। इसलिए, राजनीतिक कारणों से भारत विरोध की लहर चल रही है, जो कि काफी निंदनीय है।

ऐसे लोग गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। वे अपने ही देश में हालात को और मुश्किल बना रहे हैं। चाहे वह समाज हो या उनका धर्मनिरपेक्षता की नीति का विरोध हो।₹कुमार सचदेव ने कहा, ₹वो दिखाना चाहते हैं कि जो भारत है, बांग्लादेश उसका उल्टा है। यह बड़ा ही सहज तरीका है, क्योंकि उनके पास उपलब्धियों के नाम पर बहुत कम चीजें हैं। उनके पास नकारात्मक उपलब्धियां हैं और जनअसंतोष को विपरीत करने के लिए उसकी दिशा बदलने के लिए भारत जैसे बड़े पड़ोसी के ऊपर दोषारोपण करना चाहते हैं। यह एक अल्पकालिक तरीका है। बांग्लादेश भारत के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी भारत पर काफी निर्भरता है।'

बांग्लादेश से जुड़े खतरे की चिंता को लेकर उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथियों की जो परिस्थितियां बन रही हैं, उससे भारत को अपने पड़ोसी और पड़ोस के राज्यों में दूर तक भी एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्याएं नई नहीं हैं। भारत ने पिछले 40 सालों में कई बार भारत के बाहर से आतंकवाद का सामना किया है। बांग्लादेश से पहले भी सामना किया जा चुका है और यह फिर से परिस्थितियां इस तरह से जटिल हो जाती हैं, और बांग्लादेश एक पनाह की जगह बन जाती है, जो भारत पर हजारों टुकड़ों में प्रतिघात करना चाहता है। भारत को इससे सावधान रहने की जरूरत है।'

# मॉस्को: कार बम धमाके में रूसी सेना के शीर्ष अधिकारी की मौत, यूक्रेन पर शक

**मास्को।** रूसी जांच समिति के मुताबिक, सोमवार को मॉस्को में एक कार बम धमाके में आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवारोव की मौत हो गई। एजेंसी ने बताया कि सरवारोव की किआ सोरेंटो कार के नीचे एक विस्फोटक लगाया गया था।

रूसी जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने न्यूज एजेंसी तास को इसकी जानकारी दी।पेट्रेंको ने बताया, 'शुरुआती जांच में पता चला है कि 22 दिसंबर की सुबह, मॉस्को की यासेनेवाया स्ट्रीट पर एक कार के नीचे लगाया गया विस्फोटक डिवाइस एक्टिवेट हो गया। जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख फानिल सरवारोव इसमें सवार थे, जो कार धमाके में जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई।'

प्रवक्ता के अनुसार, मॉस्को के मुख्य जांच निदेशालय ने रूसी आपराधिक संहिता की धारा 105 के भाग 2 (सामाजिक रूप से खतरनाक तरीके से की गई हत्या) और धारा 222.1 (विस्फोटकों की अवैध तस्करी) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।उन्होंने यह भी बताया कि जांचकर्ता अलग-अलग एंगल से हत्या की वजहों पर काम कर रहे हैं। उनमें से एक थ्योरी यूक्रेन को लेकर भी है। अंदेशा है कि ये धमाका यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों की भी साजिश हो सकती है।फानिल सरवारोव का जन्म 11 मार्च, 1969 को रूस के पर्म क्षेत्र के ग्रेम्याचिंस्क में हुआ था। उन्होंने अपने सैन्य करियर के दौरान सभी प्रमुख कमांड पदों पर काम किया।2015-2016 में, उन्होंने सीरिया में सैन्य अभियानों की योजना और निष्पादन से संबंधित कार्य किए।

# ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने आतंकी घटना को लेकर यहूदी समुदाय से मांगी माफी

**नई दिल्ली।** ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर यहूदियों के खिलाफ हुए आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने माफी मांगी। बोंडी बीच पर यहूदियों के त्योहार पर आयोजित हनुक्का इवेंट में आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। पुलिस ने हमले के पीछे की प्लानिंग के बारे में नई जानकारी दी और जीवित बचे आरोपी को जेल भेज दिया। पीएम अल्बनीज ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस हमले के लिए अपनी गहरी जिम्मेदारी महसूस करते हैं।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के तौर पर, मैं उस ज़ुल्म के लिए जिम्मेदारी महसूस करता हूं जो मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ, और यहूदी समुदाय और हमारे पूरे देश ने जो अनुभव किया है, उसके लिए मुझे दुख है।"उन्होंने कहा, "सरकार यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा के लिए हर दिन काम करेगी, ऑस्ट्रेलियाई होने के नाते उनके इस बुनियादी अधिकार की रक्षा करेगी कि उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वे कौन हैं, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और ऑस्ट्रेलियाई समाज में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए।"

बता दें, पीएम अल्बनीज का ये माफीनामा ऐसे वक्त में सामने आया है, जब इजरायल की तरफ से लगातार चेतावनी को अनदेखी करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, पीएम ने हमले की जांच के लिए नेशनल रॉयल कमीशन गठित न करने के अपने फैसले का बचाव किया है।

# पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद, 8 फरवरी 2026 को ब्लैक डे मनाने का ऐलान

**इस्लामाबाद।** पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ आवाम में नाराजगी है। आए दिन धमाकों और बिगड़ते आर्थिक हालात समेत सियासी घमासान का देश पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यही वजह है कि विरोधी खेमा लामबंद हो सत्ता को चुनौती पेश करने को आतुर दिख रहा है और इसकी तपिश महसूस की जाने लगी है। विपक्षी दलों के गठबंधन तहरीक तहफुज आईन-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) ने मौजूदा सरकार की असफलताओं की फेहरिस्त बना घोषणा की है कि वो इस मनमानी का मिलकर जवाब देंगे।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस) के बाद जारी घोषणा-पत्र में, विपक्ष ने 8 फरवरी 2026 को 'ब्लैक डे' (यौम-ए-सियाह) मनाने का फैसला किया है, जो 2024 के आम चुनावों में कथित धांधली की दूसरी वर्षगांठ होगी।

स्थानीय मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है।डॉन के अनुसार, इस दिन पूरे देश में चक्का जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन और ब्लैक डे मनाने की अपील की गई।टीटीएपी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (पीकेमैप) और अन्य विपक्षी दल शामिल हैं, ने सम्मेलन में मांग की कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की स्वतंत्र नियुक्ति हो, और सत्ता का सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए।

इसमें 8 फरवरी, 2024 के चुनावों को धांधली बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई, और यह मांग की गई कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए और उन्हें दंडित किया जाए।जियो मीडिया आउटलेट के अनुसार, गठबंधन ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक संकट को गहरा कर दिया है, और नागरिक अधिकारों और अहम संस्थाओं की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। विपक्ष ने 2024 के चुनावों को 'धोखाधड़ी'और मौजूदा सरकार को 'नाजायज' बताया है।

पीटीआई प्रमुख इमरान खान और उनकी पत्नी को सुनाई गई सजा की निंदा की। इसके साथ ही खान की बहनों के साथ दुर्व्यवहार पर भी हैरानी जताई, जिसमें उनके बाल खींचने और कथित तौर पर केमिकल वाले पानी के तोपों के इस्तेमाल की घटनाएं शामिल हैं।